हिन्दी साप्ताहिक

R.N.I. No. UPHIN/2022/83621

जनता का सच

वर्ष 05 अंक 31 | लखनऊ शनिवार 08 अगस्त 2026 | पृष्ठ 04 मूल्य 2 रूपया

पीएम की एनडीए के 45 नए सांसदों के साथ बैठक

कहा- चिंता करने की जरूरत नहीं, हम साथ हैं

नई दिल्ली,एजेंसी। पीएम मोदी ने एनडीए के 45 नए लोकसभा सांसदों के साथ शुक्रवार को पीएम आवास पर ब्रेकफास्ट मीटिंग की। इनमें टीएमसी और उद्धव गुट के बागी सांसद भी थे। ममता की पार्टी टीएमसी का साथ छोड़कर 20 बागी सांसद नेशनल सिटिजन्स पार्टी ऑफ इंडिया में शामिल हो गए थे। वहीं शिवसेना (उद्धव गुट) के 6 सासंद भी शिंदे गुट के साथ आ चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, पीएम ने इन सांसदों से कहा कि एनडीए एक परिवार है। हम सहयोगी दलों के साथ हैं। हर व्यक्ति का सम्मान किया जाएगा। मैं एनडीए के हर सांसद के साथ खड़ा हूं। आपको किसी के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है।ममता बनर्जी का साथ छोड़ने वाले टीएमसी के 20 बागी सांसद लोकसभा में अलग बैठ रहे हैं। 15 जून को तृणमूल कांग्रेस के 20 सांसदों ने नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया से विलय कर लिया था वहीं 22 जून को उद्धव का साथ छोड़कर 6 सांसद शिंदे गुट में शामिल हो गए थे। ये सांसद भी अब शिंदे गुट के साथ संसद में बैठ रहें हैं। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हुआ था जो 13 अगस्त तक चलेगा।महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की शिवसेना में 22 जून को फिर बगावत हुई थी। लोकसभा के कुल 9 में से 6 सांसद पार्टी से अलग होकर डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल हो गए थे। लोकसभा में अब शिंदे के सांसदों की संख्या 7 से बढ़कर 13 हो गई है।

पीएम मोदी से दिल्ली में मिले सुखबीर बादल

नई दिल्ली,एजेंसी। शिरोमणि अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल शुक्रवार सुबह दिल्ली पहुंचे और पार्लियामेंट हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले। दोनों नेताओं की मुलाकात के बाद अकाली दल और भाजपा गठबंधन की चर्चा होने लगी है। पंजाब विधानसभा चुनाव में तकरीबन चार-पांच महीने का टाइम बचा है। माना जा रहा है कि दोनों दलों के शीर्ष नेताओं की मुलाकात के बाद अब गठबंधन फाइनल हो सकता है। इधर, मोदी-सुखबीर की मुलाकात पर आम आदमी पार्टी (क्क) सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने तंज कसा-ना ना करते प्यार तुम्हीं से कर बैठेÓ...तो क्या चन्दा चोर पार्टी और बेअदबी पार्टी का गठबंधन हो रहा है?केजरीवाल के इस तंज पर सुखबीर बादल ने कहा- 2022 से पहले क्कने दावा किया था कि आप पंजाब में फल-फूल रहे ?20,000 करोड़ के अवैध खनन को तुरंत बंद करवा देंगे और आज ह्रत्नञ्ज के आदेश ने साबित कर दिया है कि आपकी सारी गारंटी गटर में फेंकने लायक हैं। पंजाब की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने कहा- मुझे पहले से लगता था कि यह इकट्?ठे होंगे। हालांकि कोई बदलाव नहीं होगा। मुझे पता था कि टूटी बाजू इकट्ठी होंगी, लेकिन यह रहेंगी टूटी हुई ही।

संत कबीर के नाम पर पांच टेक्सटाइल पार्क और लखनऊ में 1000 एकड़ में बन रहा पीएम मित्र पार्क

हथकरघा और पावरलूम से करीब 30 लाख लोगों की आजीविका जुड़ी

लखनऊ संवाददाता। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कारीगरों व बुनकरों के उत्थान के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि यूपी में हथकरघा और पावरलूम से करीब 30 लाख लोगों की आजीविका जुड़ी है। सरकार ने 40 हजार से अधिक हस्तशिल्पियों को विद्युत सुविधा के रूप में 109 करोड़ रुपये का लाभ दिया है। सीएम ने हथकरघा उत्पादों को डिजाइन, तकनीक, पैकेजिंग व मार्केटिंग के जरिये वैश्विक बाजार से जोड़ने पर जोर दिया। उन्होंने सरकारी विभागों में हथकरघा उत्पादों की खरीद बढ़ाने और स्थानीय उत्पादों को उपहार में देने की अपील भी की। मुख्यमंत्री शुक्रवार को लोकभवन सभागार में आयोजित राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह-2026 के अवसर पर संत कबीर राज्यस्तरीय हथकरघा पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने इस अवसर पर विशिष्ट कार्यों के लिए बुनकरों को सम्मानित किया और विभिन्न योजनाओं के तहत बुनकरों व लाभार्थियों को चेक भी वितरित किए। सीएम ने कार्यक्रम स्थल पर आयोजित प्रदर्शनी का अवलोकन किया और विभिन्न उत्पादों की सराहना की। कार्यक्रम के दौरान हथकरघा उत्पादों के प्रमुख क्रेताओं के साथ समझौता ज्ञापनों का आदान-प्रदान भी किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह हमारी विरासत है। ढाई लाख परिवार यानी लगभग 14-15 लाख लोग इस व्यवसाय पर आश्रित हैं। इसमें पावरलूम को भी जोड़ लिया जाए तो यह संख्या लगभग 30 लाख तक पहुंच जाती है। हथकरघा/पावरलूम उद्योग इन 30 लाख से अधिक लोगों की आजीविका का आधार बना है। इसके जरिए लाखों लोग सरकार पर आश्रित हुए बिना ही अपने कार्यक्रम, उद्योग, रोजगार को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारी सरकार ने तय किया कि इन हस्तशिल्पियों को सम्मान मिलना चाहिए, साथ ही उन्हें हर प्रकार की सुविधा मिलनी चाहिए। इसी क्रम में गत वर्ष हैंडलूम से जुड़े हुए 40 हजार से अधिक हस्तशिल्पियों को 109 करोड़ रुपये की विद्युत से जुड़ी सुविधा उपलब्ध कराई गई है। सीएम योगी ने कहा कि यह प्रतिस्पर्धा का समय है। इस स्वस्थ प्रतिस्पर्धा में हम तभी टिक पाएंगे, जब समय व मांग के अनुरूप डिजाइन व वस्त्र तैयार करेंगे। दुनिया में उत्पादों की मांग को देखते हमारे लिए सुनहरा अवसर भी है। लखनऊ, गोरखपुर, बाराबंकी, अंबेडकर नगर, संत कबीर नगर, गोरखपुर, मऊ, आजमगढ़, वाराणसी, भदोही, मिर्जापुर समेत सभी क्षेत्र अपने उत्कृष्ट हस्तशिल्प के लिए जाने जाते हैं। हमारे कारीगरों ने स्थानीय उत्पादों को वैश्विक मान्यता व पहचान दिलाई है। प्रदेश सरकार हस्तशिल्पियों, कारीगरों व उद्यमियों के उत्थान के लिए हर वक्त साथ खड़ी है मुख्यमंत्री ने कहा कि भदोही में कालीन का क्लस्टर 2017 के पहले मृतप्राय सा हो गया था। लेकिन, आज वहां से दुनिया के बाजारों में सैकड़ों करोड़ रुपये का कालीन एक्सपोर्ट किया जा रहा है। देश की नई संसद में भी भदोही की कालीन लगी थी। देश की संसद में अलग-अलग जगहों पर उत्तर प्रदेश के हस्तशिल्प और कारीगरों का सम्मान झलकता दिखाई देता है। भदोही में केंद्र सरकार की मदद से कालीन का एक्सपो सेंटर भी बनाया है। वाराणसी में ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर की स्थापना हो चुकी है। इसके साथ ही टेक्नोलॉजी,डिजाइन, पैकेजिंग, एक्सपोर्ट, मार्केटिंग को और बेहतर बनाने के लिए भी सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। जब हम स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देंगे, तो भारत का पैसा भारत में ही लगेगा। इससे हमारे हस्तशिल्पियों के चेहरे पर समृद्धि की खुशहाली आएगी। सीएम ने कहा कि वाराणसी में फैसिलिटेशन सेंटर से जुड़े हुए छात्रों को स्कॉलरशिप दी जा रही है। गत वर्ष 450 छात्रों को स्कॉलरशिप दी गई। इसके जरिए डिजाइनिंग, टेक्नोलॉजी, पैकेजिंग के बारे में अध्ययन कराया जा रहा है। टेक्सटाइल उद्योग को मजबूती प्रदान करने के लिए लखनऊ में पीएम मित्र पार्क की स्थापना 1000 एकड़ में हो रही है। कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार प्रदान करने वाला क्षेत्र टेक्सटाइल उद्योग ही है। मुख्यमंत्री ने युवाओं और हर हाथ को काम दिलाने पर जोर देते हुए कहा कि सरकार संत कबीर के नाम पर प्रदेश में पांच स्थानों पर टेक्सटाइल पार्क की स्थापना के कार्य को आगे बढ़ा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2014 और 2017 के पहले भी विकास के ऐसे काम हो सकते थे, लेकिन इसके लिए पिछली सरकारों के पास विजन नहीं था। पिछली सरकारों में हर काम को केवल वोटबैंक के नजरिए से देखा जाता था। ऐसे में गरीबों, कारीगरों व हस्तशिल्पियों का सम्मान पिछड़ जाता था। 2017 से पहले यूपी में बिजली और आवागमन के लिए अच्छी सड़कें तक नहीं थीं। कानून-व्यवस्था इतनी बदहाल थी कि बेटी, व्यापारी, हस्तशिल्पी, कारीगर कोई भी सुरक्षित नहीं था।

देश के कई राज्यों में अगले 5-6 दिनों तक भारी बारिश के आसार

नयी दिल्ली, (एजेंसी) देशभर में दक्षिण-पश्चिम मानसून की सक्रियता के बीच दिल्ली-एनसीआर से लेकर उत्तर-पश्चिम, पूर्वी और दक्षिण भारत के विभिन्न हिस्सों में अगले 5-6 दिनों तक भारी बारिश होने का अनुमान है। वहीं, अभी भूमध्यरेखीय प्रशांत महासागर में मध्यम अल-नीनो की स्थिति बनी हुई है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार दिल्ली-एनसीआर में शनिवार सुबह से दोपहर के बीच कई जगहों पर हल्की बारिश और कुछ जगहों पर मध्यम बारिश हो सकती है। यह सिलसिला रात तक जारी रह सकता है। इस दिन का अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 33-35 डिग्री सेल्सियस और 22-24 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। रविवार और सोमवार को भी वर्षा होने से तापमान में कमी आने का अनुमान है। आईएमडी के मुताबिक, अभी भूमध्यरेखीय प्रशांत महासागर में मध्यम अल-नीनो की स्थिति बनी हुई है, जिसमें मध्य एवं पूर्वी भूमध्यरेखीय प्रशांत क्षेत्र में समुद्र की सतह का तापमान सामान्य से अधिक है। दक्षिण-पश्चिम मानसून के मौसम के दौरान इन स्थितियों के और मजबूत होने की उम्मीद है। वहीं, पश्चिम बंगाल और बंगाल की खाड़ी के तटीय इलाकों में कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। इसके असर से अगले तीन दिनों में पूर्वी भारत (ओडिशा, झारखंड, बिहार, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम, गंगा के किनारे बसे पश्चिम बंगाल) में बहुत भारी बारिश होने के आसार हैं। वहीं, अगले दो दिनों में केरल, तटीय और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में कहीं-कहीं बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। उत्तर-पश्चिम तथा उससे सटे मध्य भारत और पूर्वोत्तर भारत के कई हिस्सों में सप्ताह के अधिक दिनों में कहीं-कहीं भारी बारिश जारी रहने का अनुमान है। इसके अलावा इन्हीं क्षेत्रों में इसी बीच तेज हवाएं चलने की संभावना है, जिसकी रफ्तार 40-70 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। पिछले 24 घंटों में उत्तराखंड, पूर्वी राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और केरल में बहुत भारी बारिश (12-20 सेमी), असम, नगालैंड, अंडमान-निकोबार द्वीप समूह, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, कोंकण, तटीय कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भारी बारिश (7-11 सेमी) दर्ज की गई।

हंगामे के बीच एमएसएमई संशोधन विधेयक लोकसभा से पारित

नीट पेपर लीक और छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर सरकार पर हमलावर विपक्ष

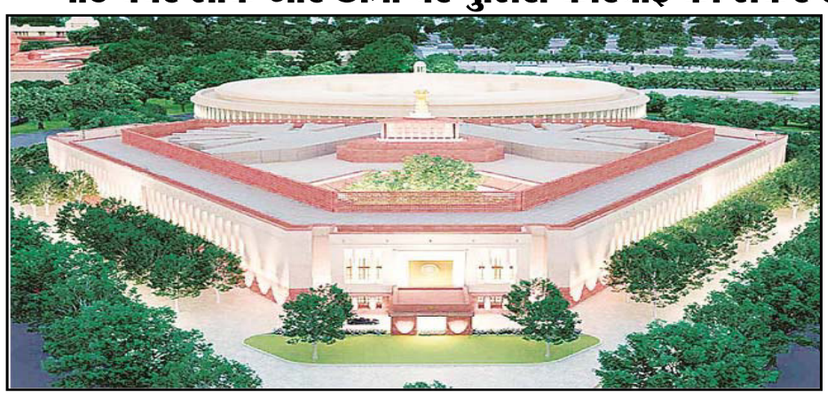

नई दिल्ली,एजेंसी। संसद के मानसून सत्र का 15वां दिन भी शुक्रवार को सरकार और विपक्ष के बीच जारी गतिरोध की भेंट चढ़ गया। लोकसभा और राज्यसभा में विपक्षी सांसदों ने हृश्वश्वज्ञ पेपर लीक, छात्रों के प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई और अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी के मुद्दे पर जमकर नारेबाजी की। विपक्ष लगातार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से सदन में बयान देने की मांग करता रहा। हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही सोमवार, 10 अगस्त तक स्थगित करनी पड़ी।

लोकसभा में हंगामे के बीच MSME विधेयक पारित

लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सांसदों ने 20 जुलाई को जंतर-मंतर की ओर मार्च कर रहे छात्रों के खिलाफ हुई कथित पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया। कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने स्थगन प्रस्ताव देकर मामले पर चर्चा और गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग की। उन्होंने पुलिस कार्रवाई की जांच और छात्रों पर दर्ज एफआईआर वापस लेने की मांग भी उठाई।

विपक्षी सांसद लगातार नारेबाजी करते रहे। इसके चलते प्रश्नकाल प्रभावित हुआ और शून्यकाल भी करीब 16 मिनट में स्थगित करना पड़ा। इसके बावजूद सरकार ने विधायी कामकाज आगे बढ़ाया और लोकसभा ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास (संशोधन) विधेयक, 2026 पारित कर दिया। यह विधेयक पहले राज्यसभा से पारित हो चुका था। हंगामे के बीच विधेयक पर विस्तृत बहस नहीं हो सकी। सदन में विभिन्न संसदीय समितियों की रिपोर्ट और कागजात भी रखे गए।

राज्यसभा में खरगे ने उठाया शाह की गैरमौजूदगी का मुद्दा

राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की सदन में मौजूदगी को लेकर सवाल उठाया। विपक्ष ने आरोप लगाया कि छात्रों के प्रदर्शन पर हुई पुलिस कार्रवाई जैसे गंभीर मुद्दे पर गृह मंत्री को सदन में आकर जवाब देना चाहिए। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि विपक्ष यह तय नहीं कर सकता कि कौन-सा मंत्री सदन में कब उपस्थित हो और किस विषय पर जवाब दे। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री संसद में उपस्थित रहते हैं और देर तक काम करते हैं।

इसके बाद भी विपक्षी सांसदों की नारेबाजी जारी रही। सभापति की अपील के बावजूद सदन में व्यवधान नहीं थमा और राज्यसभा को पहले दोपहर 12 बजे तक तथा बाद में दिनभर के लिए स्थगित कर दिया गया।

राम मंदिर चढ़ावा मामले पर भी विपक्ष का प्रदर्शन

संसद परिसर में विपक्षी सांसदों ने आज अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी का मुद्दा भी उठाया। महाराष्ट्र के कांग्रेस सांसदों ने सिद्धिविनायक मंदिर में कथित डोनेशन घोटाले को लेकर मकर द्वार पर प्रदर्शन किया। संसद के भीतर भी विपक्ष ने राम मंदिर से जुड़े मामले को सरकार के सामने उठाया। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने संकेत दिया कि विपक्ष FCRA संशोधन विधेयक का जोरदार विरोध करेगा। कांग्रेस का आरोप है कि इस विधेयक का असर ह्लह्ल और अल्पसंख्यक समुदायों पर पड़ेगा।

यूएसबीआरएल से कश्मीर को मिली हर मौसम में रेल संपर्क सुविधा

नई दिल्ली,एजेंसी। सरकार ने शुक्रवार को राज्यसभा में कहा कि उधमपुर-श्रीनगर-बारामूला रेल लिंक (यूएसबीआरएल) परियोजना के चालू होने से कश्मीर घाटी को देश के शेष हिस्सों से हर मौसम में रेल संपर्क मिल गया है। इससे सेब, सूखे मेवे, पश्मीना शॉल और हस्तशिल्प जैसे स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय बाजार तक पहुंच मिली है तथा किसानों, छोटे एवं मंझोले उद्यमों (एमएसएमई) और स्थानीय कारोबार को नया प्रोत्साहन मिला है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि 272 किलोमीटर लंबी यूएसबीआरएल परियोजना के पूरा होने से जम्मू-कश्मीर के उधमपुर, रियासी, रामबन, श्रीनगर, अनंतनाग, पुलवामा, बडगाम और बारामूला जिले भारतीय रेल नेटवर्क से जुड़ गए हैं। कटरा से श्रीनगर के बीच यात्रा समय घटकर लगभग तीन घंटे रह गया है, जिससे पर्यटन और आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि यह परियोजना स्वतंत्रता के बाद देश की सबसे कठिन रेल परियोजनाओं में से एक रही है। इसके तहत रियासी जिले में चिनाब नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बनाया गया है, जिसकी ऊंचाई नदी तल से 359 मीटर है। इसी परियोजना में अंजी खड्ड पर भारतीय रेलवे का पहला केबल-स्टेड रेल पुल भी निर्मित किया गया है। परियोजना के दौरान स्थानीय लोगों की सुविधा के लिए लगभग 215 किलोमीटर लंबी सड़कें, अनेक पुल और सुरंगों का भी निर्माण किया गया।सरकार ने बताया कि जम्मू-कश्मीर में रेल अवसंरचना के विस्तार के लिए जम्मू-रियासी-पुंछ के बीच 190 किलोमीटर नई रेल लाइन तथा जम्मू-श्री माता वैष्णो देवी कटरा अतिरिक्त रेल लाइन के लिए अंतिम स्थान सर्वेक्षण (एफएलएस) स्वीकृत किया गया है। जालंधर कैंट-जम्मू तवी तीसरी रेल लाइन के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार की जा चुकी है।

नवाचार के साथ मानवीय मूल्यों को दें प्राथमिकता :प्रह्लाद जोशी

भुवनेश्वर में 13वीं ब्रिक्स शिक्षा मंत्रियों की बैठक में पांच प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर साझा घोषणा अपनाई गई

नई दिल्ली, एजेंसी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने ब्रिक्स सहयोग में भारत की 'जन-केंद्रित और मानवता-प्रथम' (पीपुल-सेंट्रिक एंड ह्यूमैनिटी-फर्स्ट) दृष्टिकोण के प्रति प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि शिक्षा व्यवस्था को भविष्य की पीढ़ियों की आकांक्षाओं के अनुरूप निरंतर विकसित करने के लिए नवाचार अनिवार्य है। जोशी ने शुक्रवार को ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में आयोजित 13वीं ब्रिक्स शिक्षा मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक का समापन 13वीं ब्रिक्स शिक्षा मंत्रियों की घोषणा को अपनाने के साथ हुआ। बैठक को संबोधित करते हुए जोशी ने कहा कि भारत वर्ष 2026 की अपनी ब्रिक्स अध्यक्षता के विषय 'बिल्डिंग फॉर रेजिलिएंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी' के अनुरूप सभी सदस्य देशों के साथ मिलकर कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि शिक्षा प्रणाली को युवाओं को उभरते अवसरों के लिए तैयार करना चाहिए लेकिन उसे मानवीय मूल्यों से भी जुड़ा रहना होगा। नीति निर्माण और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के केंद्र में विद्यार्थियों, शिक्षकों, शोधकर्ताओं और युवाओं को रखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि शिक्षा समावेशी विकास और साझा समृद्धि की आधारशिला है तथा बैठक में अपनाई गई घोषणा ब्रिक्स देशों की पांच प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने की सामूहिक प्रतिबद्धता को दर्शाती है। उन्होंने पारंपरिक और स्वदेशी ज्ञान प्रणालियों के संरक्षण एवं संवर्धन पर भी जोर देते हुए कहा कि नवाचार और विरासत एक-दूसरे के पूरक हैं। जोशी ने कहा कि ब्रिक्स देशों की समृद्ध सभ्यतागत परंपराएं पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण, उसके वैज्ञानिक अध्ययन और भावी पीढ़ियों तक उसके हस्तांतरण का महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करती हैं। उन्होंने ओडिशा की प्राचीन शिक्षा परंपरा तथा भारत के अतिथि देवो भवः और वसुधैव कुटुम्बकम् जैसे मूल्यों का भी उल्लेख किया। बैठक में ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया, ईरान, इथियोपिया और संयुक्त अरब अमीरात सहित ब्रिक्स सदस्य देशों के शिक्षा मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक में अपनाए गये घोषणापत्र में शिक्षा को ब्रिक्स सहयोग का प्रमुख स्तंभ बताते हुए भारत की अध्यक्षता के दौरान निर्धारित पांच प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए साझा कार्ययोजना तय की गई।

पुलवामा और पहलगाम आतंकी हमलों के बाद उठाए गए कूटनीतिक और सैन्य कदमों का सरकार ने किया उल्लेख

आतंकवाद बंद, तभी सामान्य होंगे रिश्ते: जयशंकर

नयी दिल्ली एजेंसी। केन्द्र सरकार ने शुक्रवार को लोकसभा में कहा कि पाकिस्तान के साथ सामान्य द्विपक्षीय संबंध तभी संभव हैं, जब वह सीमा पार आतंकवाद, शत्रुता और हिंसा से मुक्त माहौल सुनिश्चित करे। सरकार ने स्पष्ट किया कि सीमा पार आतंकवाद और उससे जुड़ा ढांचा समाप्त करना भारत की स्पष्ट और अटल नीति है। विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि पाकिस्तान के साथ भारत के संबंध आतंकवाद, शत्रुता और हिंसा से मुक्त माहौल में ही आगे बढ़ सकते हैं। हालांकि, पाकिस्तान से प्रायोजित सीमा पार आतंकवाद अब भी जारी है और आतंकवाद का इस्तेमाल भारत के विरुद्ध आधिकारिक नीति के रूप में किया जा रहा है। सरकार ने कहा कि पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान से मोस्ट फेवर्ड नेशन (एमएफएन) का दर्जा वापस ले लिया था तथा पाकिस्तान से आयातित सभी वस्तुओं पर सीमा शुल्क बढ़ाकर 200 प्रतिशत कर दिया गया था। इसके बाद पाकिस्तान ने भी भारत के साथ राजनयिक संबंधों को कम करने और द्विपक्षीय व्यापार निलंबित करने जैसे एकपक्षीय कदम उठाए। उत्तर में कहा गया कि 22 अप्रैल 2025 को पाकिस्तान प्रायोजित पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने कई राजनयिक कदम उठाए। इनमें सिंधु जल संधि को स्थगित करना, अटारी में चेक पोस्ट को बंद करना, वीजा सेवाओं पर रोक लगाना तथा दोनों देशों के राजनयिक मिशनों में अधिकारियों की संख्या कम करना शामिल है। इसके साथ ही पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर (पीओके) में स्थित आतंकी ठिकानों के खिलाफ सैन्य कार्रवाई भी की गई। सरकार ने बताया कि वर्तमान में दोनों देशों में एक-दूसरे की राजधानियों में सीमित स्तर पर राजनयिक मिशन कार्यरत हैं। दोनों देशों के बीच केवल आवश्यक कार्यात्मक संपर्क जारी हैं, जिनमें महानिदेशक सैन्य संचालन (डीजीएमओ) स्तर की वार्ता, बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षणों की पूर्व सूचना का आदान-प्रदान, परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान-प्रदान तथा एक-दूसरे की हिरासत में मौजूद मछुआरों और नागरिक कैदियों की जानकारी साझा करना शामिल है।

बिहार में सुशासन की कसौटी पर भरत तिवारी प्रकरण

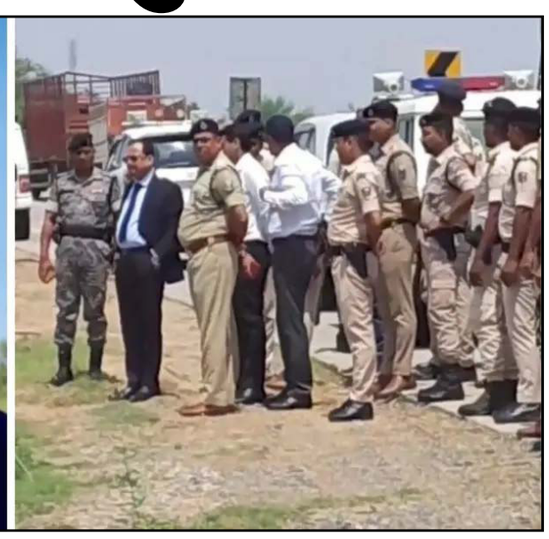

डॉ. अरविंद नाथ तिवारी
****

लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति राज्य की दंडात्मक क्षमता नहीं बल्कि कानून का शासन होता है। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की विश्वसनीयता इस बात पर निर्भर करती है कि न्याय कानून की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार हो, न कि संदेह, शक्ति या दबाव के आधार पर। जब किसी पुलिस मुठभेड़ पर गंभीर प्रश्न उठने लगें, जब न्यायिक प्रक्रिया से पहले गोलियों की गूंज सुनाई दे और जब देश के सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता सार्वजनिक मंच से गंभीर आरोप लगाएँ, तब वह घटना केवल एक व्यक्ति की मृत्यु का मामला नहीं रह जाती बल्कि शासन, प्रशासन और न्याय व्यवस्था की विश्वसनीयता की परीक्षा बन जाती है। भोजपुर जिले के बिलौटी गांव में हुए भरत तिवारी एनकाउंटर ने बिहार की राजनीति और प्रशासन के सामने ऐसे ही अनेक सवाल खड़े कर दिये हैं। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता संजीव कुमार सिंह ने मीडिया के समक्ष दावा किया है कि यह कोई सामान्य पुलिस मुठभेड़ नहीं थी। उन्होंने आरोप लगाया कि पूरे घटनाक्रम के पीछे जवइनिया गांव के विस्थापितों के लिए आई लगभग 1400 करोड़ रुपये की राशि से जुड़े कथित वित्तीय घोटाले को छिपाने का उद्देश्य था आरोपों की सत्यता का निर्णय केवल सक्षम न्यायालय अथवा निष्पक्ष जांच एजेंसी ही कर सकती है। इसलिए किसी भी पक्ष को दोषी या निर्दोष घोषित करना अभी न्यायोचित नहीं होगा। लेकिन यह भी उतना ही सत्य है कि इतने गंभीर आरोपों को केवल सरकारी बयान या औपचारिक स्पष्टीकरण से खारिज नहीं किया जा सकता। लोकतंत्र में पारदर्शिता केवल प्रशासनिक औपचारिकता नहीं, बल्कि जनता के विश्वास की आधारशिला होती है। यदि जनता के मन में संदेह पैदा हो जाय तो उस संदेह का समाधान निष्पक्ष जांच से ही संभव है। बिहार लंबे समय से ÷सुशासन÷ की राजनीति का दावा करता रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की राजनीतिक पहचान कानून-व्यवस्था, प्रशासनिक सुधार और जवाबदेह शासन के आधार पर बनी है। भारतीय जनता पार्टी भी सुशासन, पारदर्शिता और भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्रवाई को अपनी प्रमुख राजनीतिक प्रतिबद्धताओं में शामिल करती रही है। ऐसे में यदि किसी पुलिस मुठभेड़ पर व्यापक संदेह पैदा होता है तो उसका प्रभाव केवल पुलिस विभाग तक सीमित नहीं रहता बल्कि पूरी शासन व्यवस्था की साख पर पड़ता है। भारतीय संविधान प्रत्येक नागरिक को जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार देता है तथा यह सुनिश्चित

> **यदि कोई व्यक्ति गंभीर अपराधों का आरोपी भी हो, तब भी उसे न्यायिक प्रक्रिया से गुजरने का अधिकार प्राप्त है। लोकतंत्र में पुलिस का दायित्व अपराधियों को कानून के समक्ष प्रस्तुत करना है, न कि स्वयं अभियोजन, न्यायाधीश और दंडाधिकारी की भूमिका निभाना। यही कारण है कि देश की सर्वोच्च अदालत भी विवादित पुलिस मुठभेड़ों की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की आवश्यकता पर बार-बार बल देती रही है। भरत तिवारी प्रकरण में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह नहीं है कि वह निर्दोष थे या दोषी। वास्तविक प्रश्न यह है कि क्या बिहार में कानून की प्रक्रिया पर जनता का भरोसा पहले जैसा बना हुआ है? यदि जनता को यह महसूस होने लगे कि न्यायिक प्रक्रिया के स्थान पर मुठभेड़ ही अंतिम रास्ता बनती जा रही है, तो लोकतंत्र की बुनियाद कमजोर होगी। कानून का शासन केवल अपराधियों को दंडित करने से नहीं, बल्कि न्यायिक प्रक्रिया की निष्पक्षता बनाए रखने से मजबूत होता है।**

करता है कि किसी भी व्यक्ति के अपराध का निर्धारण न्यायालय करेगा, पुलिस नहीं। यदि कोई व्यक्ति गंभीर अपराधों का आरोपी भी हो, तब भी उसे न्यायिक प्रक्रिया से गुजरने का अधिकार प्राप्त है। लोकतंत्र में पुलिस का दायित्व अपराधियों को कानून के समक्ष प्रस्तुत करना है, न कि स्वयं अभियोजन, न्यायाधीश और दंडाधिकारी की भूमिका निभाना। यही कारण है कि देश की सर्वोच्च अदालत भी विवादित पुलिस मुठभेड़ों की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की आवश्यकता पर बार-बार बल देती रही है। भरत तिवारी प्रकरण में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह नहीं है कि वह निर्दोष थे या दोषी। वास्तविक प्रश्न यह है कि क्या बिहार में कानून की प्रक्रिया पर जनता का भरोसा पहले जैसा बना हुआ है? यदि जनता को यह महसूस होने लगे कि न्यायिक प्रक्रिया के स्थान पर मुठभेड़ ही अंतिम रास्ता बनती जा रही है, तो लोकतंत्र की बुनियाद कमजोर होगी। कानून का शासन केवल अपराधियों को दंडित करने से नहीं, बल्कि न्यायिक प्रक्रिया की निष्पक्षता बनाए रखने से मजबूत होता है। राजनीतिक दृष्टि से भी यह मामला अत्यंत महत्वपूर्ण है। विपक्ष स्वाभाविक रूप से इसे सरकार की जवाबदेही से जोड़ेगा। वहीं, सरकार के पास यह अवसर भी है कि वह निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध जांच कराकर यह संदेश दे कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। यदि जांच निष्पक्ष होगी और दोषी पाये जाने वाले किसी भी व्यक्ति पर बिना भेदभाव कार्रवाई होगी, तो जनता का विश्वास और मजबूत होगा, लेकिन यदि जांच की निष्पक्षता पर ही प्रश्न उठते रहे, तो यह विवाद सरकार की राजनीतिक छवि पर दीर्घकालिक प्रभाव छोड़ सकता है। हाल के राजनीतिक घटनाक्रमों, विशेषकर उपचुनावों के परिणामों को लेकर भी विभिन्न प्रकार के विश्लेषण सामने आ रहे हैं। कुछ विश्लेषक इन्हें जनता के बदलते राजनीतिक मूड से जोड़ रहे हैं। हालांकि किसी एक चुनाव परिणाम को सीधे इस प्रकरण से जोड़ना उचित नहीं होगा, क्योंकि चुनाव अनेक स्थानीय, सामाजिक और राजनीतिक कारणों से प्रभावित होते हैं। फिर भी इतना स्पष्ट है कि आज का मतदाता केवल विकास योजनाओं और घोषणाओं से संतुष्ट नहीं होता। वह न्याय, पारदर्शिता, संवैधानिक मूल्यों और जवाबदेही को भी उतना ही महत्व देता है। लोकतंत्र में सरकारें केवल चुनाव जीतने से मजबूत नहीं होतीं बल्कि जनता के विश्वास से होती हैं। यह विश्वास तभी कायम रहता है जब न्याय केवल किया ही न जाय, बल्कि निष्पक्ष रूप से होता हुआ दिखाई भी दे। भरत तिवारी प्रकरण का अंतिम सत्य जो भी हो, बिहार के हित में यही आवश्यक है कि पूरे मामले की स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी जांच हो, यदि ऐसा होता है तो न केवल सच्चाई सामने आयेगी, बल्कि कानून के शासन और सुशासन की अवधारणा भी मजबूत होगी, यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी अपेक्षा है और यही बिहार की शासन व्यवस्था के सामने वास्तविक कसौटी भी।

संम्पादकीय

नशे के विरुद्ध एक अभियान

देश को नक्सलवाद-माओवाद के आतंक से मुक्ति दिलाने के बाद केंद्र सरकार ने दो नये अहम अभियान प्रारंभ किये हैं- पहला, भारत को घुसपैठियों से मुक्त करना और दूसरा, युवाओं को नशे की लत से मुक्ति दिलाना। भारत के किशोरों तथा युवाओं को हर प्रकार के नशे से मुक्ति दिलाने के लिए 2 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी ने 卐नशा मुक्त युवा, विकसित भारत संकल्प अभियान卐 का प्रारंभ करते हुए वीडियो संदेश जारी किया है। अपने सन्देश में प्रधानमंत्री ने कहा कि जो युवा नशे से लड़कर बाहर निकलते हैं वे कमजोर नहीं बल्कि असली योद्धा होते हैं। समाज को उनका सम्मान करना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि भारत में ड्रग्स की सप्लाई दुश्मन देशों की आतंकी साजिश का हिस्सा है। दुश्मन देश भारतीय युवाओं को नशे के जाल में धकेलना चाहते हैं ताकि भारत कभी भी एक सशक्त एवं विकसित देश के रूप में स्थापित न हो सके। इस साजिश को हम सबको मिलकर नाकाम करना होगा। विकसित भारत का लक्ष्य तभी पूरा होगा जब देश का युवा शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होने के साथ नशे से भी दूर रहेगा। अगले 100 सप्ताह तक हर रविवार को कला, संस्कृति, खेल और अन्य गतिविधियों के माध्यम से नशामुक्ति का संदेश देशभर में पहुंचाया जाएगा। नशे की लत युवाओं के सपनों और परिवार दोनों को ही तोड़ देती है। नशा केवल व्यक्ति या परिवार को नहीं बल्कि राष्ट्र की ताकत को भी कमजोर करता है। इस अभियान का उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करना और उन्हें अपने समाज में बदलाव लाने के लिए आगे बढ़ाना है। प्रत्येक रविवार को देशभर में अलग-अलग कार्यक्रम होंगे जिसमें वॉकाथन और दौड़, खेल प्रतियोगिताएं, योग और ध्यान सत्र, सांस्कृतिक कार्यक्रम, नुक्कड़ नाटक, नशा विरोधी जागरूकता अभियान, चर्चा और संवाद कार्यक्रम, पेंटिंग्स व आर्ट्स प्रतियोगिताएं तथा सामुदायिक सहभागिता कार्यक्रम आयोजित किये जाएंगे। यह अभियन 125 से अधिक आध्यात्मिक, सामाजिक तथा सरकारी संगठनों के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। ब्रहमकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, आर्ट ऑफ़ लिविंग, गायत्री परिवार, इस्कॉन से लेकर माता अमृतानंदमयी मठ जैसे संगठन इस अभियान से जुड़ कर कार्य कर रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद् पहले से व्यापक स्तर पर नशामुक्ति अभियान चला रहा है। युवाओं में नशे के विरुद्ध जागरूकता लाने के साथ ही गृहमंत्री अमित शाह ने भी नशे की जड़ों पर प्रहार करने का युद्ध छेड़ रखा है। ड्रग्स माफियाओं के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। तस्करी करके बड़ी मात्रा में विदेशों से आने वाली ड्रग्स की जब्ती बंदरगाहों तथा एयरपोर्ट्स की जा रही है और उसे नष्ट किया जा रहा है। वर्ष 2021 में 2988 किलो हेरोइन, 2022 में 927 किलो गांजा, 2023 में 122 किलो मेफेड्रोन, 2024 में 770 किलो मेथाफाटेमाइन और 2026 में फिर 522 किलो गांजा बरामद किया जा चुका है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अनुसार 2020 से मई 2025 तक तक 116 बड़े मामलों में कार्रवाई करते हुए 1,09,318 किलोग्राम नशीले पदार्थ जब्त किए गए हैं और उनको नष्ट किया गया है।

ढाका की राजनीति और भारत-बांग्लादेश संबंधों की नई परीक्षा

-: ललित गर्ग:-
****

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना द्वारा दिसंबर 2026 में स्वदेश लौटने की घोषणा केवल एक राजनीतिक बयान नहीं है, बल्कि यह दक्षिण एशिया की बदलती भू-राजनीति, लोकतांत्रिक मूल्यों और भारत-बांग्लादेश संबंधों की दिशा तय करने वाला एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम बन गया है। जिस समय बांग्लादेश की राजनीति सत्ता परिवर्तन, वैचारिक ध्रुवीकरण और संस्थागत अस्थिरता के दौर से गुजर रही है, उसी समय शेख हसीना ने यह घोषणा कर राजनीतिक विमर्श को एक नए मोड़ पर ला खड़ा किया है। उनका यह कहना कि 'गिरफ्तारी, जेल या मृत्यु का भय भी उन्हें अपने देश लौटने से नहीं रोक सकता', उनके समर्थकों के लिए भावनात्मक आह्वान है तो विरोधियों के लिए एक बड़ी राजनीतिक चुनौती। बांग्लादेश में पिछले वर्ष सत्ता परिवर्तन के बाद जो राजनीतिक वातावरण बना, उसमें लोकतांत्रिक संस्थाओं की निष्पक्षता और राजनीतिक सहिष्णुता पर लगातार प्रश्न उठते रहे हैं। बांग्लादेश में अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण द्वारा शेख हसीना के विरुद्ध सुनाया गया फैसला और उसके बाद उनके समर्थकों पर बढ़ती कार्रवाइयों ने यह संकेत दिया कि राजनीतिक प्रतिस्पर्धा धीरे-धीरे प्रतिशोध की राजनीति में बदलती जा रही है। हाल ही में उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल रहे पूर्व क्रिकेट कप्तान साकिब अल हसन के घर पर हुआ हमला भी इस बात का संकेत

है कि राजनीतिक असहमति अब सामाजिक तनाव का रूप लेने लगी है। दूसरी ओर, प्रधानमंत्री तारिक रहमान के एक करीबी सहयोगी द्वारा शेख हसीना को 'तुरंत लौटकर सामना करने' की चुनौती देना बताता है कि बांग्लादेश का राजनीतिक वातावरण अभी भी सामान्य नहीं हुआ है। लोकतंत्र में किसी भी राजनीतिक दल या नेता से असहमति स्वाभाविक है, किंतु असहमति का समाधान न्यायपूर्ण राजनीतिक प्रक्रिया और स्वतंत्र संस्थाओं के माध्यम से होना चाहिए। यदि किसी नेता की लोकप्रियता का उत्तर प्रतिबंध, दमन या भय के वातावरण से दिया जाए, तो लोकतंत्र की आत्मा कमजोर होती है। शेख हसीना की वापसी को केवल एक व्यक्ति की वापसी के रूप में नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक प्रतिस्पर्धा की परीक्षा के रूप में देखा जाना चाहिए। यदि अवामी लीग को राजनीतिक प्रक्रिया से बाहर रखने की कोशिश होती है, तो यह बांग्लादेश के लोकतंत्र की विश्वसनीयता पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगाएगा। वास्तविकता यह भी है कि बांग्लादेश की राजनीति आज केवल अवामी लीग और बांग्लादेश नेशनललिस्ट पार्टी (बीएनपी) के बीच सत्ता संघर्ष तक सीमित नहीं रह गई है। अब यह संघर्ष राष्ट्र की ऐतिहासिक पहचान, 1971 के मुक्ति संग्राम की विरासत और भविष्य की वैचारिक दिशा का भी बन चुका है। अवामी लीग स्वयं को मुक्ति संग्राम की मूल चेतना का प्रतिनिधि बताती है, जबकि बीएनपी भी अब उसी विरासत पर अपना दावा प्रस्तुत कर रही है। इतिहास की इस प्रतिस्पर्धी व्याख्या ने राजनीतिक ध्रुवीकरण को और गहरा किया है। ऐसी परिस्थितियों में शेख हसीना की वापसी केवल राजनीतिक समीकरण नहीं बदलेगी, बल्कि राष्ट्रीय विमर्श की दिशा भी प्रभावित करेगी इन परिस्थितियों में भारत की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। भारत और बांग्लादेश के संबंध केवल दो पड़ोसी देशों के रिश्ते नहीं हैं, बल्कि साझा इतिहास, संस्कृति, भाषा, आर्थिक सहयोग और सामरिक हितों पर आधारित हैं। पिछले डेढ़ दशक में दोनों देशों के संबंधों में अभूतपूर्व निकटता आई, जिसका एक बड़ा आधार शेख हसीना सरकार और नई दिल्ली के बीच बना विश्वास था। सीमा विवादों का समाधान, ऊर्जा सहयोग, संपर्क परियोजनाएं, आतंकवाद के विरुद्ध साझा कार्रवाई तथा पूर्वोत्तर भारत की कनेक्टिविटी जैसे अनेक क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति हुई। लेकिन वर्तमान राजनीतिक परिवर्तन ने इस विश्वास की नई परीक्षा शुरू कर दी है। नई दिल्ली ने एक ओर शेख हसीना को सुरक्षा और आश्रय दिया है, वहीं दूसरी ओर उसने ढाका की नई सरकार से संवाद भी जारी रखा है। यही परिपक्व कूटनीति का परिचायक है। भारत के सामने चुनौती किसी एक राजनीतिक दल के साथ खड़ा दिखाई देने की नहीं, बल्कि पूरे बांग्लादेश के साथ स्थायी और संतुलित संबंध बनाए रखने की है। इसी संदर्भ में नई दिल्ली में आयोजित होने वाला बारहवाँ ब्रिक्स शिखर सम्मेलन अत्यंत महत्वपूर्ण अवसर बन सकता है। यदि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान इसमें भाग लेते हैं और भारत के शीर्ष नेतृत्व के साथ सकारात्मक संवाद होता है, तो दोनों देशों के बीच हाल के तनावों को कम करने का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। यह केवल औपचारिक शिखर बैठक नहीं होगी, बल्कि दोनों देशों के बीच विश्वास बहाली का अवसर भी होगी। भारत को इस मंच का उपयोग केवल आर्थिक सहयोग तक सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि क्षेत्रीय स्थिरता, लोकतांत्रिक मूल्यों और सुरक्षा सहयोग पर भी स्पष्ट संवाद स्थापित करना चाहिए भारत के सामने अनेक जटिल प्रश्न भी हैं। गंगा जल संधि के नवीनीकरण, तीस्ता जल बंटवारे, सीमा-पार व्यापार, अवैध घुसपैठ, सीमा सुरक्षा तथा शेख हसीना के प्रत्यर्पण जैसे मुद्दे आने वाले समय में द्विपक्षीय संबंधों की दिशा तय करेंगे। इनमें किसी भी विषय पर भावनात्मक या राजनीतिक प्रतिक्रिया के बजाय कानूनी, कूटनीतिक और व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक होगा। विशेष रूप से प्रत्यर्पण का प्रश्न केवल कानूनी प्रक्रिया नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय कानून और राजनीतिक परिस्थितियों से भी जुड़ा हुआ है। भारत को अपनी संधियों, न्यायिक प्रक्रियाओं और रणनीतिक हितों के बीच संतुलन बनाकर आगे बढ़ना होगा। दूसरी ओर बांग्लादेश में चीन का बढ़ता प्रभाव भी नई दिल्ली के लिए चिंता का विषय है। वर्तमान सरकार के शुरुआती महीनों में चीन के साथ बढ़ते संपर्क और सामरिक महत्व की परियोजनाओं पर समझौते इस बात का संकेत हैं कि ढाका अपनी विदेश नीति में संतुलन साधने का प्रयास कर रहा है। भारत के लिए आवश्यक है कि वह प्रतिस्पर्धा की मानसिकता के बजाय विश्वास और विकास की साझेदारी को प्राथमिकता दे। यदि भारत आर्थिक सहयोग, निवेश, आधारभूत संरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य और तकनीकी साझेदारी के नए अवसर विकसित करता है, तो दोनों देशों के संबंध और अधिक मजबूत हो सकते हैं।

शेख हसीना की वापसी का प्रश्न अंततः बांग्लादेश के लोकतांत्रिक चरित्र की परीक्षा है। यदि उन्हें निष्पक्ष राजनीतिक अवसर मिलता है, तो जनता स्वयं तय करेगी कि भविष्य का नेतृत्व किसे सौंपना है। लेकिन यदि राजनीतिक प्रतिशोध, दमन और हिंसा का वातावरण बना रहता है, तो इससे न केवल बांग्लादेश की लोकतांत्रिक साख प्रभावित होगी, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया की स्थिरता पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। भारत को इस पूरे घटनाक्रम में संयम, संतुलन और दूरदृष्टि के साथ आगे बढ़ना होगा। न तो उसे किसी आंतरिक राजनीतिक विवाद का पक्षकार बनना चाहिए और न ही लोकतांत्रिक मूल्यों की उपेक्षा करनी चाहिए।

आज का राशिफल

निकट संबंधों में शंकाओं को हावी न होने दें। भौतिक आकांक्षाओं की पूर्ति होने के आसार बनेंगे। नौकरी का वातावरण सुखद होगा। सगे-संबंधों में प्रगाढ़ता बढ़ेगी।

डॉ. प्रियंका सौरभ

हरियाणा के जींद जिले में नौगामा खाप की महापंचायत द्वारा प्रेम विवाह करने वाले जोड़ों

आर्थिक क्षेत्र में लाभ के आसार हैं। अवरोधित कार्य हल होंगे। योजनाओं के फलीभूत होने से मन प्रसन्न होगा। विद्यार्थियों के लिए ग्रहों की अनुकूलता लाभप्रद होगी।

बीती बातों को भूलने की कोशि करें। रोजगार में कुछ अच्छे अवसर मिलेंगे। भौतिक इच्छाएं बलवती होंगी। अभिभावकों के भावनात्मक सहयोग से उत्साह में वृद्धि होगी।

नकारात्मक चिंताओं का त्याग करें। महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां अपनी पूर्ति हेतु मन पर दबाव बनाएंगी। वर्तमान में आपको सकारात्मक सोच के साथ सकारात्मक दिशा में प्रयास करना चाहिए।

महत्वाकांक्षाएं मन पर प्रभावी होंगी। घरेलू कायरें में अत्याधिक व्यय का योग है। कार्यक्षेत्र में व्यस्तता बढ़ेगी। परिवार में सुखद स्थिति प्रसन्नता लाएगी।

किसी नये कार्य की ओर आपका रुझान बढ़ेगा। किसी महत्वपूर्ण फैसले के लिए मन केंद्रित होगा। नवीन योजनाओं द्वारा प्रगति होगी। जीवन साथी के साथ मधुरता कायम रखें।

परिश्रम का समुचित लाभ प्राप्त होगा। पारिवारिक वातावरण सुखद व उत्साहपूर्ण होगा। महत्वपूर्ण योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु प्रयत्न तीव्र होगा।

मन सुंदर कल्पनाओं से प्रभावित रहेगा। नये संबंधों के प्रति निकटता बढ़ेगी। उपस्थित साधनों में सन्तुष्ट व तृप्त होने का प्रयत्न करें। जीवन साथी के स्वास्य के प्रति सतर्कता अपेक्षित है।

राजनीति से जुड़े लोगों के लिए समय अनुकूल रहेगा। अच्छे कायरे के लिए प्रशंसनीय होंगे। शासन-सत्ता से लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने में मन दुविधाग्रस्त होगा।

विभागीय परिवर्तनों से कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अपने अन्दर धैर्य व वाणी में मधुरता लावें। कुछ नई अभिलाषाएं मन में जागृत होंगी। प्रियजनों का सनिध्य प्राप्त होगा।

आवोश में किये गये कार्य से कष्ट संभव। भावनात्मक समस्याओं पर सगे-संबंधियों के बीच खुलकर बात करें। कुछ नये उत्साह व कार्य क्षमता की अनुभूति करेंगे।

मशीन फिर से अपने पुराने ढर्रे पर चलने लगती है

सतीश झा
****

बच्चा एक ऐसी थाली के सामने बैठा है, उसके सामने इंसानियत के पूरे ज्ञान का इतिहास एक ही बार में परोस दिया गया हो और कहा गया हो–लो, खाओ। थाली भरी हुई है। लेकिन, ध्यान से देखें तो वह पूरी तरह खाली है। ज्जब बारह साल बाद एक बच्चा बाहर निकलता है और वह एक पैराग्राफ़ पढ़ नहीं पाता या एक मामूली घटाव नहीं कर पाता, तो आप उँगली किस पर उठाएँगे? कोई एक वादा टूटा ही नहीं, सारे वादे एक साथ किए गए थे और सब एक-दूसरे में घुलकर गायब हो गए। जब भी हिंदुस्तानी व्यवस्था का कोई खंभा दरकता है, तो उसका धुआँ अपने तय समय पर ही दिखाई देता है। पहले वह नाकामी आती है, जो सालों से किसी अंधेरे कोने में सुलग रही होती है–किसी परीक्षा बोर्ड का खामोश सड़ांध मारता ढाँचा, छपने से पहले ही बिकता प्रश्नपत्र, या एक रात में पूरे देश पर थोप दी गई वह नीति, जिस पर किसी ने सलाह तक करने की ज़हमत नहीं उठाई। फिर उठती हैं लपटें, और उन लपटों की रोशनी खींच लाती है तमाशबीनों की भीड़–राजधानी के चौराहों पर जुटे बिलखते छात्र, जेठ की धूप में गाढ़ा होता आँसू गैस का धुआँ, भूख हड़तालें और ऐसा विपक्ष, जो व्यवस्था के हर ज़ख्म में अपनी जीत का वोट तलाशने लगता है। और सबसे आखिर में, मानसून की तरह अपने तय समय पर टिप्पणियों का सिलसिला शुरू होता है। लेखक, अर्थशास्त्री, नीतियाँ बनाने वाले और उनकी आलोचना करने वाले–सब अपनी-अपनी ऐनक साफ़ करके मैदान में उतर आते हैं। हर किसी की जेब में एक बना-बनाया नुस्खा तैयार है। एक साहब को इसमें ऐसी सरकार की तानाशाही दिखती है, जो चुनाव जीतना तो सीख गई, पर संस्थाएँ चलाना भूल गई। दूसरे को दिखता है कि व्यवस्था अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों से कैसे चुपके से पीछे हट रही है–जहाँ मुफ़्त शिक्षा के अधिकार को बिकने वाली चीज़ बना दिया गया है। तीसरे साहब नीति-निर्माताओं की %नैतिकता' को खोखला भावुक तर्क बताकर खारिज करते हैं और कहते हैं कि मामला सिर्फ़'व्यवस्था का है–यानी स्कूल जो बना रहे हैं और बाज़ार जो खरीद रहा है, उनके बीच का टकराव। चौथे साहब दुनिया की दौड़ की ऊँचाई से देखकर हैरान होते हैं कि जो देश मशीनों के युग में बच्चों से पुरानी भाषाएँ रटवा रहा है, वह एक साधारण परीक्षा भी बिना चोरी के नहीं करा सकता। पाँचवें साहब इस पूरी तबाही को तीन शब्दों में बाँध देते हैं–सांप्रदायिकीकरण, व्यापारीकरण और केंद्रीकरण–और परीक्षा एजेंसी के सफाए तथा मंत्री की बलि की माँग करने लगते हैं। छठे साहब इस पूरे तामझाम को दिमागों के %उपनिवेश-मुक्ति' की महान क्रांति बताते हैं और विरोध की उठती आवाज़ों में कोचिंग माफिया की साज़िश ढूँढ़ लेते हैं। अपने-अपने ढाँचे में हर कोई सही है। और सच पूछिए, तो असली आफ़त यही है। पढ़ने वाला एक ही साँस में इन दलीलों से गुजरता है, हर बात पर सिर हिलाता है और इस संतोष के साथ उठ खड़ा होता है कि उसने सब कुछ समझ लिया–सिवाय इसके कि कुछ बदलने वाला क्यों नहीं है। इन तमाम पंडितों की लेखनी में एक ही समानता है–निशाना। सब उस चीज़ पर तीर चला रहे हैं, जो ठीक आँखों के सामने है–लीक हुआ प्रश्नपत्र, ताज़ा आदेश, सड़कों पर जमा भीड़ और कटघरे में खड़ा मंत्री। सब असर पर हमला कर रहे हैं, वजह पर नहीं। हमारे बुद्धिजीवियों ने खुद को बीमारी के लक्षणों का सुंदर वर्णन करने वाला ऐसा बारीक औजार बना लिया है कि वह बयानबाज़ी ही अपने आप में एक नशा बन चुकी है। जो देश अपनी बीमारी का नाम छह अलग-अलग भाषाओं में लेना सीख जाए, उसे इलाज की कोई जल्दी नहीं रहती। यह बहस किसी सुधार की तरफ़ नहीं ले जाती; यह बहस तो असल में उस सुधार की जगह लेने वाला नशा है। धुएँ के पीछे जलती इमारत को देखने के बजाय, ज़रा उस ढाँचे को देखिए, जिसे बनाया ही जलने के लिए गया था। कुछ साल पहले मैंने भारतीय कक्षा की तुलना एक थाली से की थी। बच्चा एक ऐसी थाली के सामने बैठा है, जो बेहिसाब पकवानों से भरी पड़ी है–दर्जनों विषय, तीन-तीन भाषाएँ और ऐसा पाठ्यक्रम, मानो दस साल के बच्चे के सामने इंसानियत के पूरे ज्ञान का इतिहास एक ही बार में परोस दिया गया हो और कहा गया हो–लो, खाओ। थाली भरी हुई है। लेकिन, ध्यान से देखें तो वह पूरी तरह खाली है। दुनिया का कोई बच्चा उस थाली से अपना पेट नहीं भर सकता। जो परोसा गया है, वह खाना नहीं–खाने का केवल भ्रम है। मैंने अपनी किताब का नाम रखा था–द फुल प्लेट। मुझे लगा था कि मैं व्यवस्था की एक भूल का ज़िक्र कर रहा हूँ। लेकिन असल में मैं उसके एक चालाक समाधान की व्याख्या कर रहा था। थाली भूल से भारी नहीं की गई है। उसे जान-बूझकर ऐसे भरा गया है, क्योंकि जो व्यवस्था सब कुछ देने का दावा करती है, उस पर किसी एक नाकामी का आरोप नहीं लगाया जा सकता। जब बारह साल बाद एक बच्चा बाहर निकलता है और वह एक पैराग्राफ़ पढ़ नहीं पाता या एक मामूली घटाव नहीं कर पाता, तो आप उँगली किस पर उठाएँगे? कोई एक वादा टूटा ही नहीं, सारे वादे एक साथ किए गए थे और सब एक-दूसरे में घुलकर गायब हो गए।यह फैलाव कोई उदारता नहीं है। यह तो जिम्मेदारी को इतने छोटे-छोटे टुकड़ों में बाँट देना है कि नाकामी का कोई एक सुराग ही न मिले। जिसकी नाप-जोख न हो सके, उस पर अदालत कैसे चले? भरी हुई थाली दरअसल ऐसा बही-खाता है, जिसे इतना उलझा दिया गया है कि कोई उसका ऑडिट ही न कर सके। यह किसी अफ़सर की नालायकी नहीं है। यह तो इस मशीन का असली डिज़ाइन है, जो ठीक वैसा ही काम कर रहा है, जैसा उसे करने के लिए बनाया गया था। और यही बात सबसे ज्यादा डरावनी है। क्योंकि नालायकी सुधारी जा सकती है, पर अपने मकसद में सफल मशीन को उसकी फितरत से बाज़ नहीं लाया जा सकता। ज़रा गौर से देखिए कि यह मशीन कर क्या रही है? इसने पढ़ाई की कसौटी को पूरी तरह %परीक्षा की कसौटी' से बदल दिया है। ये दोनों बातें कभी एक नहीं थीं, और अब इनके बीच इतनी दूरी आ चुकी है कि एक पूरी समानांतर अर्थव्यवस्था उसी खाली जगह में फल-फूल रही है, जहाँ पास होने' और जानने' का सौदा होता है।परीक्षा ही अब अकेला दरवाज़ा बन चुकी है। और क्योंकि वही अकेला दरवाज़ा है, इसलिए समाज की हर ताकत उसी पर टूट पड़ती है–लीक होते प्रश्नपत्र, मुन्ना भाइयों के गिरोह, कोचिंग की दुकानें और खरीदे गए नतीजे।

जो विश्लेषक लीक होते प्रश्नपत्रों पर माथा पीटते हैं, वे पाइप के दबाव को पाइप की खराबी समझ बैठते हैं।

हूती विद्रोहियों का बड़ा हमला; यमन के 58 सैनिकों की मौत, सऊदी अरब में 11 घायल

सना/रियाद,। यमन के हूती विद्रोहियों ने यमन और सऊदी अरब में एक साथ कई मिसाइल एवं ड्रोन हमले किए हैं। यमन के हद्रामौत और मारिब प्रांतों में हुए हमलों में 58 सैनिकों की मौत हो गई, जबकि दर्जनों अन्य घायल हुए हैं। वहीं, सऊदी अरब के नजरान क्षेत्र में हुए हमले में चार वर्षीय बच्चे सहित 11 नागरिक घायल हुए हैं। हमलों के बाद दोनों देशों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है।रिपोर्टों के अनुसार हूती विद्रोहियों ने मारिब के उत्तर में स्थित अल-जॉफ प्रांत से आठ बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं, जिनका निशाना हद्रामौत के अल-थिनिया और अल-अब्र क्षेत्रों के साथ मारिब के अल-रौक क्षेत्र में स्थित सैन्य ठिकाने थे। भारतीय समयानुसार गुरुवार शाम लगभग साढ़े चार बजे हुए इन हमलों में हद्रामौत स्थित सरकारी सैन्य इकाइयों, होमलैंड शील्ड फोर्सेज, आपातकालीन बलों तथा कई सैन्य शिविरों को निशाना बनाया गया।

बताया जा रहा है कि वर्ष 2022 के बाद यमन पर यह सबसे भीषण हमला है। हमलों में बड़ी संख्या में सैनिकों के हताहत होने की पुष्टि की गई है।

उधर, सऊदी अरब के दक्षिणी नजरान क्षेत्र में हुए मिसाइल हमले में 11 नागरिक घायल हुए हैं। घायलों में सात सऊदी नागरिक, एक यमनी, दो मिस्र के नागरिक तथा एक पाकिस्तानी नागरिक शामिल हैं। हमले के बाद नजरान के कई हिस्सों में आग लग गई। आग की ऊंची लपटें और धुएं का गुबार दूर-दूर तक दिखाई दिया। प्रारंभिक आशंका है कि आग मिसाइल हमले के कारण लगी।सऊदी नेतृत्व वाले सैन्य गठबंधन के प्रवक्ता मेजर जनरल तुर्की अल-मलिकी ने कहा कि गठबंधन नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाता रहेगा और सुरक्षा बल स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं।हूती विद्रोहियों के प्रवक्ता याह्या सारी ने हमलों की जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि यह कार्रवाई सऊदी अरब के समर्थन से कथित रूप से की जा रही सैन्य तैयारियों के जवाब में की गई है। उन्होंने यह भी दावा किया कि विद्रोहियों ने नजरान हवाई अड्डे को भी निशाना बनाया।

यमन के रक्षा मंत्रालय ने हमलों की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि इस हमले का जवाब उचित समय और उचित स्थान पर दिया जाएगा।

यमन स्थित अमेरिकी दूतावास ने इन हमलों को कायरतापूर्ण करार दिया है। दूतावास ने एक वक्तव्य में हमले में मारे गए यमनी सैनिकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि इस प्रकार की हिंसक कार्रवाई यमन की जनता के खिलाफ आतंकवाद का एक और उदाहरण है।उधर, इन घटनाओं के बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर सऊदी अरब के दौरे पर हैं। दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को लेकर पहले से समझौता लागू है। ऐसे में क्षेत्रीय सुरक्षा की दृष्टि से इन हमलों को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

कैलिफोर्निया में अकेले ट्रेकिंग पर निकले भारतीय मूल के लापता शोध छात्र का शव मिला

वाशिंगटन/कैलिफोर्निया, अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में ट्रेकिंग के दौरान लापता हुए भारतीय मूल के शोध छात्र विक्रम मुबायी का शव इन्यो राष्ट्रीय वन क्षेत्र से बरामद किया गया है। वह पिछले दो दिनों से लापता थे। पुलिस ने फिलहाल किसी आपराधिक साजिश की आशंका से इनकार किया है, हालांकि मामले की विस्तृत जांच जारी है।विक्रम मुबायी कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, सांता बारबरा के रॉबर्ट मेहराबियन अभियांत्रिकी महाविद्यालय में रासायनिक अभियांत्रिकी विषय में शोध कर रहे थे। सप्ताहांत के दौरान वह बिग पाइन लेक्स क्षेत्र में अकेले ट्रेकिंग के लिए गए थे।परिजनों के अनुसार, विक्रम ने एक अगस्त की रात लगभग साढ़े आठ बजे अंतिम बार परिवार से बातचीत की थी। उन्होंने ट्रेकिंग के दौरान अपनी वैश्विक स्थिति निर्धारण प्रणाली (जीपीएस) के माध्यम से अपनी स्थिति भी साझा की थी। इसके बाद उनसे संपर्क नहीं हो सका।जब सप्ताहांत समाप्त होने के बाद भी विक्रम वापस नहीं लौटे, तो परिवार ने उनसे संपर्क करने का प्रयास किया। उनका मोबाइल फोन बंद मिला और संदेशों का भी कोई उत्तर नहीं मिला। इसके बाद परिजनों ने स्थानीय प्रशासन को सूचना दी।सूचना मिलने पर इन्यो काउंटी खोज एवं बचाव दल तथा कैलिफोर्निया राजमार्ग गश्ती दल ने संयुक्त रूप से व्यापक खोज अभियान शुरू किया। अभियान के दौरान तीन अगस्त को बिग पाइन लेक्स क्षेत्र के जंगल में विक्रम का शव बरामद किया गया।प्रारंभिक जानकारी के अनुसार शव जल क्षेत्र के पास मिला है। हालांकि वह पानी तक कैसे पहुंचे और उनकी मृत्यु किन परिस्थितियों में हुई, इसका अभी तक स्पष्ट पता नहीं चल पाया है।

असम के संकट में झारखंड बना संबल : हेमंत सोरेन ने भेजा 3 करोड़ का चेक, हिमंता बिस्वा सरमा ने जताया आभार

रांची, एजेंसी। असम में आई विनाशकारी बाढ़ से हुए भारी नुकसान के बीच झारखंड सरकार ने मदद का हाथ बढ़ाया है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड की जनता की ओर से असम के मुख्यमंत्री राहत कोष में 3 करोड़ रुपये की सहायता राशि उपलब्ध कराई है. मुख्यमंत्री ने 5 अगस्त को इस संबंध में असम के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर बाढ़ प्रभावित परिवारों के प्रति गहरी संवेदना भी व्यक्त की.लोगों और संस्थाओं से भी सहयोग की अपीलः मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड के सक्षम नागरिकों, सामाजिक संस्थाओं और अन्य संगठनों से भी अपील की है कि वे अपनी क्षमता के अनुसार असम के बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद के लिए आगे आएं. उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदा के इस कठिन समय में एक-दूसरे का साथ देना ही सबसे बड़ी जिम्मेदारी है.असम के जल्द सामान्य होने की कामनाः मुख्यमंत्री ने असम के लोगों के साहस, धैर्य और सेवा-भाव की सराहना करते हुए मां कामाख्या से प्रार्थना की कि राज्य जल्द इस आपदा से उबरकर सामान्य जनजीवन की ओर लौटे. उन्होंने भरोसा जताया कि सामूहिक प्रयासों से असम इस संकट से बाहर निकलेगा और जरूरत पड़ने पर झारखंड हर संभव सहयोग के लिए हमेशा तैयार रहेगा.असम सीएम हिमंता बिस्वा सरमा ने जताया हार्दिक आभारः झारखंड की ओर से मिली इस सहायता पर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट साझा कर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और झारखंड की जनता का आभार व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि असम और झारखंड के बीच वर्षों पुराने आत्मीय संबंध हैं और दोनों राज्यों ने हर सुख-दुःख में एक-दूसरे का साथ दिया है।

राजस्थान में मूक-बधिर छात्र-छात्राओं का प्रदर्शन, गहलोत और जूली पहुंचे स्कूल

जयपुर, एजेंसी। जयपुर के आनंदीलाल पोद्दार मूक-बधिर उच्च माध्यमिक स्कूल में दिव्यांग छात्र-छात्राओं ने पीने के पानी के संकट, जर्जर स्कूल भवन, शौचालयों की बदहाल स्थिति और शिक्षकों द्वारा तय समय पर पढ़ाई नहीं करवाने को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। छात्र-छात्राओं ने स्कूल के बाहर रास्ता रोक लिया, जिसे प्रशासनिक अधिकारियों के समझाने के बाद खाली करवाया। सूचना मिलने पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एवं विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता टीकाराम जूली भी स्कूल में पहुंचे। छात्र-छात्राओ ने आरोप लगाया कि कई ऐसे शिक्षक स्कूल में तैनात हैं, जिन्हें साइन भाषा नहीं आती है। विरोध प्रदर्शन के दौरान कुछ छात्र-छात्राएं बीमार भी हो गए, जिनका चिकित्सकों ने उपचार किया। हंगामा बढ़ता देखकर जिला कलेक्टर संदेश नायक एवं शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारी मौके पर पहुंचे।

मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटा रही पुलिस, भड़के युसूफ पठान; अमित शाह से लगाई गुहार

नई दिल्ली, एजेंसी। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। तृणमूल कांग्रेस छोड़कर 'एनसीपीआई' में शामिल हुए तीन बागी सांसदों ने अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से इस मामले में तत्काल दखल देने की गुहार लगाई है। बहरामपुर से सांसद और पूर्व क्रिकेटर युसूफ पठान समेत तीन सांसदों ने गृह मंत्रालय को ज्ञापन सौंपकर पुलिस की इस कार्रवाई को रोकने की मांग की है।

अमित शाह से क्या बोले तीनों सांसदः 2024 के लोकसभा चुनाव में टीएमसी के टिकट पर चुनाव जीतने वाले बहरामपुर के सांसद युसूफ पठान, मुर्शिदाबाद के सांसद अबू ताहेर खान और जंगीपुर के सांसद खलीलुर रहमान ने गुरुवार को गृह मंत्री के कार्यालय को एक संयुक्त ज्ञापन सौंपा। सांसदों ने ज्ञापन में कहा है कि वे शोर नियंत्रण पर कानून और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पूरी तरह से सम्मान करते हैं। हालांकि, सरकार को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि नियमों का पालन 'निष्पक्ष, एक समान और संवेदनशील' तरीके से हो, ताकि किसी की धार्मिक भावनाएं आहत न हों।

क्या है पूरा विवाद और पुलिस की दलीलः दरअसल, पश्चिम बंगाल से ऐसी खबरें आ रही थीं कि स्थानीय पुलिस द्वारा मस्जिदों से अजान के लिए इस्तेमाल होने वाले लाउडस्पीकर जबरन हटाए जा रहे हैं। इसी के विरोध में सांसदों ने यह कदम उठाया है। दूसरी ओर, इस मामले में पश्चिम बंगाल पुलिस का कहना है कि यह कार्रवाई किसी एक समुदाय के खिलाफ नहीं की जा रही है। ध्वनि प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल) के आदेशों के तहत सभी धार्मिक स्थलों पर समान रूप से नियमों को लागू किया जा रहा है। बता दें कि ये तीनों सांसद उन 20 सांसदों के समूह में शामिल हैं, जिन्होंने टीएमसी का साथ छोड़कर एनसीपीआई का दामन थामा है। एनसीपीआई एक गैर-मान्यता प्राप्त पार्टी है, जिसने त्रिपुरा में दो विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था और इसे चंद सौ वोट ही मिले थे। यह पार्टी बीजेपी का समर्थन करती है। हालांकि, बंगाल के मुस्लिम बहुल मुर्शिदाबाद जिले से आने वाले इन तीनों मुस्लिम सांसदों ने हाल ही में एनडीए की बैठकों से दूरी बना ली थी। उनका स्पष्ट कहना था कि वे ऐसे किसी भी कानून का समर्थन नहीं करेंगे जो मुसलमानों के हितों के खिलाफ जाता हो।

वोटर लिस्ट से 4.55 लाख नाम कटने का भी उठाया मुद्दा

लाउडस्पीकर विवाद के अलावा, इन सांसदों ने मतदाता पहचान पत्र ट्रिब्यूनल के लंबित मामलों में हो रही भारी देरी का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया। सांसदों ने बताया कि कई असली मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए हैं और वे ट्रिब्यूनल के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। इस देरी की वजह से आम लोगों को पासपोर्ट वेरिफिकेशन, जमीन की रजिस्ट्री और सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने में भारी परेशानी हो रही है। सांसदों ने मांग की है कि इस साल के अंत तक सभी लंबित और असली मामलों का तेजी से निपटारा किया जाए। गौरतलब है कि चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक, 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची के विशेष सघन पुनरीक्षण

पूर्व सीएम की बेटी ने पुलिसवाले को काट लिया, कर दिया घायल; केस दर्ज

श्रीनगर, एजेंसी। जम्मू-कश्मीर पुलिस ने बीते मंगलवार को श्रीनगर में विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस अधिकारी पर कथित तौर पर हमला करने के आरोप में पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की नेता इल्तिजा मुफ्ती को समन भेजा है। जानकारी के मुताबिक पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा ने एक पुलिसवाले के साथ मारपीट की, उसके हाथ पर काटा और उसे घायल कर दिया। इसके बाद उन कर केस दर्ज कर लिया गया है।

गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के साल साल पूरे होने पर 4 अगस्त की शाम पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती और पार्टी नेता इल्तिजा मुफ्ती के नेतृत्व में एक विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया गया था। पुलिस का आरोप है कि इस दौरान कुछ प्रदर्शनकारियों ने रेजीडेंसी रोड को जाम कर लाल चौक की तरफ बढ़ने की कोशिश की और पुलिस के बैरिकेड्स को भी नुकसान पहुंचाया। इसी दौरान इल्तिजा ने पुलिस संग मारपीट की।

पुलिसवाले के हाथ पर काटने के आरोपः पुलिस का दावा है कि इस दौरान हुई हाथापाई में इल्तिजा मुफ्ती ने ड्यूटी पर तैनात एक पुलिस अधिकारी से मारपीट की और उनके हाथ पर काट लिया। इससे अधिकारी को बड़ी चोट आई और खून बहने लगा। घायल अधिकारी को तुरंत अस्पताल ले जाकर इलाज करवाया गया। इस मामले में महबूबा और उनकी बेटी दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया कि उनके खिलाफ लोक सेवक पर हमले और आधिकारिक कार्य में बाधा डालने के आरोप में कोठीबाग थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। जांच के तहत इल्तिजा को शुक्रवार को कोठीबाग थाने में हाजिर होने का आदेश दिया गया है।

अजी और फजी, कश्मीर में कौन से नारे लगे कि बैकफुट पर आ गई भाजपा दे रही

जम्मू, एजेंसी। जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने की 7वीं बरसी के मौके पर अनंतनाग में निकाली गई एक रैली विवादों में आ गई है। इस रैली में लगाए गए नारों को लेकर विपक्ष ने तीखी प्रतिक्रिया दी है और इसे कश्मीरी महिलाओं का अपमान बताया है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने और भारी विरोध-प्रदर्शन के बाद, जम्मू-कश्मीर बीजेपी ने अब इन नारों से किनारा कर लिया है।

क्या है पूरा मामलाः 5 अगस्त 2019 को जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निरस्त कर उसे दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया था। बुधवार को इसकी सातवीं बरसी थी। इस दिन जहां बीजेपी ने जश्न मनाया, वहीं विपक्षी दलों ने 5 अगस्त को 'काला दिन' के रूप में मनाया। अनुच्छेद 370 हटने का जश्न मनाने के लिए जुलूस निकालने की अनुमति केवल बीजेपी को मिली थी। इसी के तहत अनंतनाग में जम्मू-कश्मीर बीजेपी के उपाध्यक्ष सोफी

यूसुफ की अगुवाई में एक जश्न रैली निकाली गई। आरोप है कि इस जुलूस के दौरान सोफी यूसुफ और उनके समर्थकों ने कुछ ऐसे नारे लगाए जो आपत्तिजनक थे। इन नारों का वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर सामने आया, लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। अनंतनाग के बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रैली में कश्मीरी में नारे लगाए। इनमें 'अजी और फजी' शब्दों का इस्तेमाल किया गया। 'अजी और फजी' को कश्मीरी महिलाओं से जोड़कर देखा जाता है।

विपक्ष ने लगाया महिलाओं के अपमान का आरोपः विपक्षी दलों ने बीजेपी पर महिलाओं के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। दशकों से घाटी में अनुच्छेद 370 से जुड़े जिन नारों और कविताओं को स्थानीय संस्कृति में सम्मान के तौर पर देखा जाता था, उन पर इस रैली में कथित तौर पर तंज कसा गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता तनवीर सादिक ने तीखा हमला बोलते हुए कहा, 'कुछ अपमान सिर्फ किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए होते हैं।' उन्होंने कहा कि 'अजी और फजी' कोई मामूली नाम नहीं हैं, बल्कि ये उस सम्मान, स्नेह और गरिमा के प्रतीक हैं जिससे कश्मीर हमेशा अपनी माताओं और बहनों को देखता आया है। सादिक ने जनता से अपील करते हुए कहा, 'जब ये और इनकी ए, बी और सी टीमें आपके दरवाजे पर आएं, तो याद रखिएगा कि वे किस बात का मजाक उड़ा रहे थे। जो लोग अपना स्वाभिमान खो देते हैं, वे सब कुछ खो देते हैं। '

घिरी बीजेपी ने दी सफाई, नारों से किया किनाराः सोशल मीडिया पर भारी आक्रोश और विपक्ष के हमलों के बाद बीजेपी बैकफुट पर आ गई है। पार्टी ने आपत्तिजनक नारों से खुद को अलग करते हुए इसके लिए कुछ व्यक्तियों को जिम्मेदार ठहराया है।

बीजेपी प्रवक्ता ने एक बयान जारी कर कहा कि पार्टी महिलाओं के सम्मान के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिबद्धता को दोहराती है। पार्टी ने स्पष्ट किया, 'कुछ लोगों ने अपनी निजी सोच या भावनाओं के आधार पर नारे लगाए होंगे, लेकिन ये नारे बीजेपी के आधिकारिक रुख या रैली का नेतृत्व करने वाले नेताओं के विचारों को नहीं दर्शाते। पार्टी किसी के भी खिलाफ किसी तरह की अपमानजनक टिप्पणी का कतई समर्थन नहीं करती।

क्या विपक्ष परिसीमन बिल का समर्थन करेगा रिजिजू ने राहुल गांधी से की

नई दिल्ली, एजेंसी। संसद में गतिरोध के बीच सत्तापक्ष की तरफ से केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने गुरुवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी से फोन पर महत्वपूर्ण और विस्तृत बातचीत की. यह बातचीत मुख्य रूप से परिसीमन बिल और महिला आरक्षण बिल को लेकर हुई. सूत्रों के अनुसार, रिजिजू ने राहुल गांधी को स्पष्ट रूप से बताया कि सरकार परिसीन बिल में विपक्ष का समर्थन चाहती है, ताकि महिला आरक्षण बिल को जल्द से जल्द लागू किया जा सके. बातचीत के दौरान किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी से कहा कि यह मुद्दा महिलाओं के अधिकारों से जुड़ा है. उन्होंने जोर देकर कहा कि अगर विपक्ष परिसीमन बिल में सहयोग करे, तो महिला आरक्षण का क्रियान्वयन सुचारू रूप से हो सकेगा. रिजिजू ने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार के पास संसद में बिल पारित करने के लिए पर्याप्त संख्या बल मौजूद है, फिर भी वह व्यापक सहमति के साथ बिल को आगे बढ़ाना चाहती है. इस पर राहुल गांधी ने जवाब दिया कि वे इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर अकेले फैसला नहीं ले सकते. उन्होंने कहा कि पहले वह

कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और अन्य गठबंधन दलों (INDJ गठबंधन) से विस्तृत चर्चा करेंगे. उसके बाद ही सरकार को अपना रुख बताएंगे. राहुल गांधी ने किरेन रिजिजू से यह भी मांग की कि सरकार सभी राजनीतिक दलों की एक औपचारिक बैठक (ऑल पार्टी मीटिंग) बुलाए. उन्होंने कहा कि ऐसी बैठक में सभी दलों के विचार सुनने के बाद ही वे कोई आधिकारिक रुख अपनाएंगे. सूत्रों के मुताबिक, रिजिजू ने साफ कहा कि सरकार फिलहाल ऑल पार्टी मीटिंग के पक्ष में नहीं है. उन्होंने राहुल गांधी से यह शर्त रखी कि अगर वे पहले से यह आश्वासन देते हैं कि ऑल पार्टी मीटिंग में विपक्ष परिसीमन बिल का समर्थन करेगा, तभी सरकार ऐसी बैठक आयोजित करने पर विचार कर सकती है, अन्यथा सरकार ऑल पार्टी मीटिंग नहीं बुलाएगी. सूत्रों ने कहा कि दोनों नेताओं के बीच फोन पर बातचीत कई मिनट तक चली. दोनों तरफ से इस मुद्दे की गंभीरता और प्राथमिकताओं पर भी बातचीत हुई. साथ ही सूत्रों की मानें तो सरकार ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से संसद में जारी गतिरोध खत्म करने का भी आग्रह किया. जिस पर राहुल ने कहा कि विपक्ष गृह मंत्री के जवाब के बाद ही सदन में सहयोग करने को राजी होगा. बहरहाल, सरकार महिला आरक्षण को जल्द लागू करने के लिए परिसीमन बिल में समर्थन चाहती है, जबकि राहुल गांधी और विपक्ष व्यापक चर्चा और सभी दलों की सहमति की मांग कर रहे हैं. फिलहाल दोनों पक्ष अपने-अपने रुख पर अड़े हुए हैं. वहीं, सूत्रों की मानें तो सरकार 12 अगस्त को एफसीआरए बिल भी लोकसभा में ला सकती है और इसपर भी वो विपक्ष का सहयोग चाहती है।

थाईलैंड के एक स्कूल में छात्र ने गोलीबारी की; 7 की मौत, खुद को खत्म किया

बैंकॉक। थाईलैंड में नोनथाबुरी प्रांत के एक स्कूल में शुक्रवार को एक छात्र ने गोलीबारी कर दी, जिसमें कम से कम 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 15 अन्य लोग घायल हो गए। घटना राजधानी बैंकाक से 20 किलोमीटर दूर प्रांत के बैंग क्रुआई जिले में घटी है। हमलावर आरोपी स्कूल का छात्र है, जिसने बाद में खुद को गोली मार ली। पुलिस कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल डेचरापी कोंगडी ने बताया कि मृतकों में 3 शिक्षक और 4 छात्र शामिल हैं।रिपोर्ट्स के मुताबिक, गोलीबारी करने वाला कक्षा 8 का छात्र था, जिसकी उम्र 14 साल की थी। उसने गोलीबारी क्यों की, इसका कारण सामने नहीं आया

है।आपातकालीन कर्मी ने बताया कि उन्हें स्कूल की ऊपरी मंजिल पर एक पुरुष शिक्षक मृत पड़ा मिला, और दूसरे कमरे में उन्हें एक महिला शिक्षक छाती और बांह में घावों के साथ मिलीं।

कई लोगों को सीपीआर देकर बचाने की कोशिश की गई। कई छात्र भगदड़ में घायल हुए हैं।

जिले के अधिकारियों ने बताया कि 2025 के शैक्षणिक वर्ष में स्कूल में लगभग 3,100 छात्र और 147 शिक्षक नामांकित थे।थाईलैंड में इस क्षेत्र में बंदूक रखने की दर सबसे अधिक है, जहां अनुमानित तौर पर लगभग एक करोड़ आग्नेयास्त्र प्रचलन में हैं, यानी हर 7 निवासियों पर एक के पास हथियार है।घटना के बाद सामने आई तस्वीरों में देबसिरिन नोनथाबुरी स्कूल से घायल छात्रों को स्ट्रेचर पर ले जाते देखा गया है।इससे पहले, फरवरी में दक्षिणी थाईलैंड के हाट याई जिले में एक बंदूकधारी ने स्कूल पर गोलीबारी की थी, जिसमें प्रधानाचार्य की मौत हो गई और 2 छात्र घायल हुए थे। बाद में किशोर शूटर गिरफ्तार कर लिया गया।2022 में, बंदूक और चाकू से लैस एक पूर्व पुलिसकर्मी ने एक नर्सरी में घुसकर 24 बच्चों और 12 वयस्कों की हत्या कर दी, जो थाईलैंड के सबसे घातक नरसंहारों में से एक है।

उत्तर प्रदेश के लिए बनेगी नई युवा नीति, युवाओं की राय से तैयार होगा रोडमैप; राज्य युवा आयोग गठन पर भी विचार

लखनऊ, । मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के युवाओं के समग्र विकास के लिए एकीकृत युवा नीति तैयार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि यह नीति युवाओं की बदलती अपेक्षाओं, आकांक्षाओं और भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाई जाएगी। इसके साथ ही युवाओं से जुड़ी योजनाओं की सतत निगरानी, मूल्यांकन और सुझाव देने के लिए विशेषज्ञों की सहभागिता वाला स्वतंत्र राज्य युवा आयोग गठित करने की संभावनाओं पर भी विचार किया जाएगा।मुख्यमंत्री ने अपने सरकारी आवास पर आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में कहा कि युवा नीति तैयार करने से पहले 16 से 35 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं की आवश्यकताओं और अपेक्षाओं को समझना जरूरी है। इसके लिए विद्यार्थियों, खिलाड़ियों, शोधार्थियों, स्टार्टअप उद्यमियों, युवा पेशेवरों तथा विभिन्न वर्गों के युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही सार्वजनिक माध्यमों से भी सुझाव आमंत्रित किए जाएंगे, ताकि नीति वास्तविक जरूरतों और

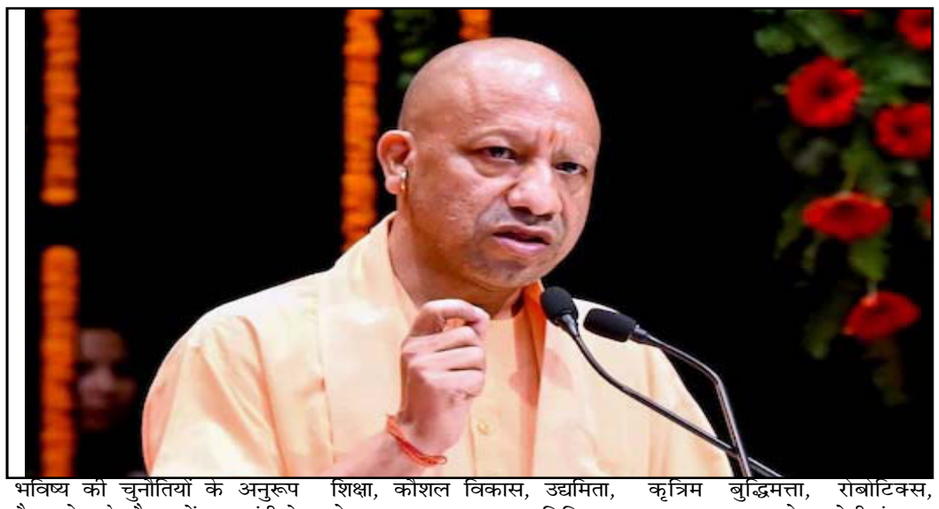

भविष्य की चुनौतियों के अनुरूप शिक्षा, कौशल विकास, उद्यमिता, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स, रोजगार, नवाचार, डिजिटल सशक्तीकरण, स्वास्थ्य, खेल, नेतृत्व विकास तथा संस्कृति और विरासत जैसे सभी महत्वपूर्ण विषयों को समग्र रूप से शामिल किया जाएगा।मुख्यमंत्री ने कहा कि भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए युवाओं को आधुनिक तकनीकों के अनुरूप प्रशिक्षित करना समय की मांग है। उन्होंने तैयार हो सके।बैठक में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि प्रदेश में युवाओं के लिए संचालित सभी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रत्येक पात्र युवा तक योजनाओं का लाभ समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से पहुंचे। प्रस्तावित युवा नीति में साइबर सुरक्षा, ड्रोन, सेमीकंडक्टर और अन्य उभरते क्षेत्रों में कौशल विकास कार्यक्रमों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रत्येक जनपद में उद्यमिता और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अनुकूल वातावरण विकसित करने, युवा उद्यमिता केंद्र स्थापित करने, स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने तथा रोजगार सृजन के प्रयास तेज करने पर जोर दिया। साथ ही युवाओं के लिए एकीकृत डिजिटल मंच विकसित करने का निर्देश दिया, जहां करियर मार्गदर्शन, छात्रवृत्ति, रोजगार मेले और अन्य सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध हो सकें।मुख्यमंत्री ने सरदार वल्लभभाई पटेल औद्योगिक एवं रोजगार क्षेत्र की स्थापना का कार्य शीघ्र प्रारंभ करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग योजना को और अधिक प्रभावी बनाने पर बल देते हुए कहा कि इसके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। इस योजना का विस्तार प्रदेश के प्रत्येक विश्वविद्यालय और महाविद्यालय तक करने की संभावनाएं तलाशने तथा युवा आईएएस, आईपीएस अधिकारियों सहित विभिन्न विशेषज्ञों की सहभागिता सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि कई प्रतिष्ठित निजी कोचिंग संस्थान उत्तर प्रदेश में अपनी इकाइयां स्थापित करने के इच्छुक हैं और इस अनुकूल माहौल का लाभ प्रदेश के युवाओं को मिलना चाहिए।बैठक में मुख्यमंत्री ने खेल गतिविधियों को युवाओं को नशे जैसी सामाजिक बुराइयों से दूर रखने का प्रभावी माध्यम बताते हुए प्रत्येक ग्राम पंचायत में खेल मैदान, प्रत्येक विकास खंड में मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, प्रत्येक जनपद में खेल उत्कृष्टता केंद्र तथा प्रत्येक मंडल में उच्च प्रदर्शन केंद्र विकसित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विधायक निधि से इनडोर स्टेडियम निर्माण की पूर्व पहल के सकारात्मक परिणाम मिले हैं और इस दिशा में कार्यों को आगे बढ़ाया जाना चाहिए।मुख्यमंत्री ने आधुनिक पुस्तकालयों, अध्ययन केंद्रों और रीडिंग स्पेस के विस्तार पर भी जोर दिया, ताकि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं को बेहतर अध्ययन वातावरण उपलब्ध कराया जा सके। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य ऐसी युवा नीति तैयार करना है, जो प्रदेश के युवाओं को आत्मनिर्भर, नवाचारी, कुशल और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए सक्षम बनाते हुए विकसित उत्तर प्रदेश और विकसित भारत के निर्माण में उनकी प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करे।

संक्षिप्त समाचार

अखिलेश यादव का नया 'पीडीए' केवल चुनावी अवसरवाद : रालोद

लखनऊ । राष्ट्रीय लोकदल (रालोद) के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष अनुपम मिश्रा ने समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के बुधवार को दिए बयानों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि उनका बदला हुआ 'पीडीए' का अर्थ केवल चुनावी अवसरवाद का परिचायक है। कल तक पीडीए की परिभाषा पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक बताने वाले आज चुनाव नज़दीक आते ही ब्राह्मण और अन्य सवर्ण समाज की बात करने लगे हैं। जनता इस बदलाव के पीछे की राजनीतिक मंशा को भली-भांति समझ रही है।

अनुपम मिश्रा ने कहा कि जो लोग समय-समय पर सनातन परंपरा, उसके प्रतीकों और उससे जुड़ी आस्थाओं के प्रति अनादरपूर्ण टिप्पणियों से जुड़े रहे हों, उनके मुख से आज सामाजिक समरसता और सभी वर्गों के सम्मान की बातें जनता को स्वाभाविक नहीं लगतीं। प्रदेश की जनता कथनों और वास्तविक राजनीतिक आचरण के बीच का अंतर भली-भांति समझती है। उन्होंने कहा कि आज अचानक सवर्ण समाज की चिंता जताना केवल चुनावी रणनीति का हिस्सा प्रतीत होता है। यदि यह भावना वास्तविक होती, तो यह पहले भी उनके सार्वजनिक बयानों और राजनीतिक व्यवहार में दिखाई देती। अनुपम मिश्रा ने कहा कि राष्ट्रीय लोकदल सामाजिक समरसता, सम्मान और सभी वर्गों को साथ लेकर चलने की राजनीति में विश्वास करता है। प्रदेश की जनता अब केवल नारों और बदली हुई परिभाषाओं से प्रभावित होने वाली नहीं है, बल्कि नेताओं के पिछले आचरण और कार्यों के आधार पर अपना निर्णय करेगी।

प्राथमिक शिक्षक संघ की प्रदेश कार्यसमिति बैठक ब्लॉक स्तर तक संगठन मजबूत करने पर जोर

लखनऊ । उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ की प्रदेश स्तरीय संयुक्त कार्यसमिति बैठक बुधवार को लखनऊ के राजभवन स्थित डिप्लोमा इंजीनियर्स भवन में आयोजित हुई। बैठक में प्रदेश के लगभग 72 जिलों से आए जिला अध्यक्ष, मंत्री, प्रांतीय पदाधिकारी और प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। बैठक में शिक्षकों की लंबित मांगों, नई शिक्षा नीतियों, सेवा संबंधी समस्याओं और संगठन की आगामी रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई। प्रदेश अध्यक्ष सुशील कुमार पांडे ने कहा कि टीईटी प्रकरण के कारण लाखों शिक्षकों की नौकरी प्रभावित हो रही है। कई बार ज्ञापन देने के बावजूद सरकार की ओर से कोई निर्णय नहीं लिया गया, जिससे शिक्षकों में नाराजगी है। उन्होंने पुरानी पेंशन योजना लागू कर शिक्षकों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग भी दोहराई। बैठक में विभागीय अधिकारियों के रवैये पर भी सवाल उठाए गए। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि शिक्षकों के लंबित देयकों का समय पर भुगतान नहीं हो रहा है। ऐसे मामलों में जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय कर कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि शिक्षक हितों की लड़ाई सड़क से लेकर सदन तक लड़ी जाएगी। प्रांतीय कार्यसमिति ने विद्यालयों में शैक्षणिक कार्यों के अलावा लगातार जारी हो रहे गैर-शैक्षणिक आदेशों पर रोक लगाने की मांग की। बिना स्पष्टीकरण शिक्षकों का वेतन रोके जाने पर भी आपत्ति जताई गई। इसके अलावा प्रत्येक विद्यालय में एक कंप्यूटर ऑपरेटर की नियुक्ति, कोरोना काल से बदले विद्यालय समय को पूर्ववत करने और शिक्षकों को खंड शिक्षा अधिकारी पद पर पदोन्नति देने की मांग उठाई गई। बैठक में सभी जिलों से आए जिला अध्यक्षों और मंत्रियों ने प्रदेश अध्यक्ष सुशील कुमार पांडे के नेतृत्व वाली कार्यसमिति पर एकमत से विश्वास जताया। सभी पदाधिकारियों ने हम चले मूल संगठन के साथ का नारा लगाते हुए संगठन की एकजुटता और शिक्षक हितों के लिए मिलकर संघर्ष करने का संकल्प लिया। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष सुशील कुमार पांडेय ने की। उन्होंने कहा कि संगठन को और मजबूत बनाने के लिए ब्लॉक स्तर पर सक्रिय एवं समर्पित शिक्षकों को जोड़ते हुए कार्यकारिणी का पुनर्गठन किया जाएगा। उन्होंने जिला स्तर पर एकजुट रहकर शिक्षक हितों की आवाज बुलंद करने का आह्वान किया। मुख्य अतिथि एवं संघ के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अभिमन्यु प्रसाद तिवारी ने कहा कि शिक्षकों की एकता और संघर्ष के कारण ही पंचम वेतन आयोग का लाभ मिल सका। उन्होंने शिक्षा, शिक्षक और भावी पीढ़ी के हितों के लिए सभी शिक्षकों से एकजुट होकर संघर्ष करने की अपील की। बैठक में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अभिमन्यु प्रसाद तिवारी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। पूर्व प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष राम तीर्थ मिश्रा और अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष गीता पांडे विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुई। इसके अलावा प्रांतीय कार्यसमिति के सदस्य तथा प्रदेश के लगभग 72 जिलों के जिला अध्यक्ष और मंत्री भी बैठक में मौजूद रहे।

ओवरटाइम पर मिलेगी डबल सैलरी

लखनऊ । यूपी के लाखों कामगारों और मेहनतकश मजदूरों के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और श्रमिकों के जीवन स्तर में सुधार लाने के मकसद से सरकार ने श्उत्तर प्रदेश मजदूरी संहिता नियमावलीश् को पूरी तरह से लागू कर दिया है। इस नए नियम के लागू होने के बाद अब राज्य के उद्योगों, फैक्ट्रियों और विभिन्न प्रतिष्ठानों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए ओवरटाइम करने के नियमों में बड़ा बदलाव आया है, जिससे मेहनतकशों की जेब में सीधे ज्यादा पैसे आने का रास्ता साफ हो गया है।श्रम विभाग द्वारा लागू की गई इस नई नियमावली के तहत अब यदि कोई श्रमिक अपनी निर्धारित सामान्य ड्यूटी के समय से ज्यादा यानि ओवरटाइम काम करता है, तो उसे मिलने वाला पारिश्रमिक दोगुना कर दिया गया है।

उमा शंकर सिंह की अंतिम विदाई में मायावती का छलका दर्द, बोलीं-सबने धोखा दिया, लेकिन वो नही

लखनऊ। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की अध्यक्ष मायावती ने बृहस्पतिवार को अपने दिवंगत पार्टी विधायक उमा शंकर सिंह को श्रद्धांजलि दी। मायावती ने सिंह को एक समर्पित और वफादार नेता बताया और कहा कि उनका निधन पार्टी और उनके विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए एक बड़ी क्षति है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में बसपा के एकमात्र विधायक रहे उमाशंकर सिंह (55) का बुधवार रात दिल्ली में निधन हो गया था। बलिया की रसड़ा सीट से विधायक रहे सिंह काफी समय से बीमारी से जूझ रहे थे। दिल्ली से लाए जाने के बाद सिंह का पार्थिव शरीर उनके लखनऊ स्थित आवास पर रखा गया था, जहां मायावती ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। बाद में संवाददाताओं से बातचीत में मायावती ने कहा कि

विधायक उमाशंकर सिंह ने पार्टी में शामिल होने के बाद से ही सिंह ने पूरी ईमानदारी, समर्पण और वफादारी के साथ बसपा की सेवा की और राजनीतिक उतार-चढ़ाव के बावजूद कभी पार्टी के साथ धोखा नहीं किया। मायावती ने शोकाकुल परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि इस मुश्किल समय में बसपा उनके साथ मजबूती से खड़ी रहेगी। बसपा प्रमुख ने दिवंगत विधायक के साथ अपने करीबी व्यक्तिगत संबंधों को याद करते हुए कहा कि सिंह उन्हें अपनी सगी बहन मानते थे और हर साल राखी की रस्म भी निभाते थे। मायावती ने कहा कि सिंह हमेशा लोगों के सुख-दुख में उनके साथ खड़े रहे और उनके हितों का पूरा ध्यान रखा। उन्होंने कहा, मेरा मानना घ्है कि उनके विधानसभा क्षेत्र के लोग भी यही चाहेंगे कि उनकी विरासत आगे बढ़े। उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी मायावती ने यह भी संकेत दिया कि अगर सिंह का परिवार चाहे तो पार्टी उन्हें राजनीतिक रूप से समर्थन देने को तैयार है। उन्होंने कहा, उनका एक बेटा और एक शादीशुदा बेटी है। पूरे परिवार ने हमेशा मुझे बहुत सम्मान दिया है। अगर परिवार चाहेगा, तो मैं उनके बेटे को राजनीति में मौका दूंगी और उसे पूरा समर्थन दूंगी। हालांकि, अभी ऐसी बातों पर चर्चा करने का समय नहीं है, लेकिन मैं परिवार को भरोसा दिलाना चाहती थी कि बसपा उनके साथ खड़ी है। उत्तर प्रदेश की 403 सदस्यीय विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी के एकमात्र विधायक रहे उमाशंकर सिंह का बुधवार शाम बीमारी के बाद निधन हो गया। बताया गया कि वह ब्रेन ट्यूमर का इलाज करा रहे थे।

मुंशी प्रेमचंद जयंती पर प्रेमचंद का साहित्य एवं जनमानस पर प्रभाव विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित

लखनऊ । नवयुग कन्या महाविद्यालय, राजेन्द्र नगर के हिंदी विभाग की नवज्योतिका संस्था एवं उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद की जयंती के अवसर पर एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी का मुख्य विषय श्प्रेमचंद का साहित्य एवं जनमानस पर प्रभावश् रहा। कार्यक्रम का शुभारंभ पारंपरिक रूप से दीप प्रज्वलन एवं सरस्वती वंदना के साथ हुआ। तत्पश्चात, अतिथियों को पौधे, अंगवस्त्र एवं स्मृति चिह्न भेंट कर उनका आत्मीय स्वागत किया गया। प्रथम वक्ता-प्रो. राहुल पांडे हिंदी विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, उन्होंने प्रेमचंद के विचारों को रेखांकित करते हुए कहा कि प्रेमचंद के अनुसार साहित्य सदैव उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। वे एक कालजयी लेखक थे, जिन्होंने अपने समय और समाज का विशद अध्ययन किया। उनके साहित्य में कृषक जीवन, नारी के विविध रूप, छुआछूत और सांप्रदायिकता जैसी समस्याओं का सजीव चित्रण मिलता है। उन्होंने किसानों की स्थिति पर टिप्पणी करते हुए लिखा थाकृ किसान नरम चारा है। उन्होंने छात्राओं को प्रेमचंद को गहराई से समझने के लिए अमृत राय द्वारा संपादित श्विविध प्रसंग और चिट्ठी-पत्री जैसी पुस्तकें पढ़ने का सुझाव दिया तथा कहा कि आज भी प्रेमचंद के साहित्य के श्पुनर्पाठश् की अत्यंत आवश्यकता है। गणमान्य वक्ता प्रो. माधुरी यादव, ए. पी. सेन गर्ल्स कॉलेज, ने प्रेमचंद के साहित्यिक योगदान की चर्चा करते हुए कहा कि उनका लेखन लगभग 300 वर्षों का प्रभाव समेटे हुए एक सतत साधना की तरह है। उन्होंने 12 से अधिक उपन्यास लिखे और वे हिंदी सिनेमा के भी लोकप्रिय कथाकार सिद्ध हुए। आज भी हमारे समाज में श्गोबरश् और श्मातादीनश् जैसे पात्र जीवित दिखाई देते हैं। प्राचार्या प्रो. मंजुला उपाध्याय, अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में प्राचार्या ने युवाओं को सदैव सजग और जागरूक रहने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि सत्य को जानने और समझने के लिए समाचार पत्रों तथा शोध-पत्रों (रिसर्च पेपर्स) का नियमित अध्ययन आवश्यक है। निरंतर पढ़ने-लिखने की आदत से बौद्धिक विकास होता है और विचार स्पष्ट बनते हैं। इन सभी प्रयासों का मूल उद्देश्य यह होना चाहिए कि हमारे ज्ञान और कर्म में सदैव श्राष्ट्र प्रथमश् का भाव सर्वोपरि रहे। डॉ. रश्मि शील प्रख्यात साहित्यकार ने बताया कि प्रेमचंद जी ने प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन में नए प्रकार के साहित्य के सृजन पर बल दिया था, किंतु वे उससे बहुत पहले से ही साहित्य के फलक पर नए रंग भर रहे थे। उन्होंने साहित्य को कल्पना के आकाश से उतारकर धरातल पर स्थापित किया और उसे जीवन-मूल्यों से जोड़ा। यही कारण है कि उनका साहित्य जनमानस को गहराई से प्रभावित करता है। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान से अंजू सिंह व हर्ष, काव्योंम फाउंडेशन से प्रशांत, हिन्दी विभागाध्यक्ष डॉ अंकिता पाण्डेय, डॉ मेघना यादव, डॉ अपूर्वा अवस्थी तथा महाविद्यालय की सभी प्रवक्ताएं एवं छात्राएं उपस्थित रहीं। कार्यक्रम के दौरान हिंदी विभाग एवं प्रयोजनमूलक हिंदी की छात्राओं ने मुंशी प्रेमचंद से जुड़े संस्मरणों और उनकी प्रसिद्ध कहानी बूढ़ी काकी का सुंदर वाचन किया। कार्यक्रम का कुशल एवं सफल संचालन डॉ. अंकिता पांडे ने किया। अंत में राष्ट्रगान के साथ

ग्राम संगठनों का होगा विस्तार, महिला सशक्तिकरण को मिलेगी नई गति

लखनऊ,। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के निर्देश पर उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक, सामाजिक एवं संस्थागत सशक्तिकरण को नई गति देने के उद्देश्य से प्रदेश में ग्राम संगठनों की संख्या 65,460 से बढ़ाकर 75460 किये जाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। इस संबंध में ग्राम्य विकास विभाग के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं।उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने गुरूवार को जारी बयान में कहा कि डबल इंजन सरकार ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर, स्वावलंबी और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए निरंतर प्रभावी कदम उठा रही है। स्वयं सहायता समूहों का सुदृढ़ नेटवर्क ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था की वास्तविक शक्ति है और ग्राम संगठनों का विस्तार इस दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर सिद्ध होगा।उन्होंने कहा कि ग्राम संगठनों की संख्या में वृद्धि होने से अधिक से अधिक स्वयं सहायता समूहों को संगठित ढांचे से जोड़ा जा सकेगा। इससे समूहों को समयबद्ध मार्गदर्शन, क्षमता संवर्धन, वित्तीय समावेशन, बैंकिंग सेवाओं तक बेहतर पहुंच तथा विभिन्न आजीविका गतिविधियों का अधिक प्रभावी लाभ प्राप्त होगा। साथ ही ग्राम संगठनों की संस्थागत क्षमता और कार्यकुशलता में भी उल्लेखनीय वृद्धि होगी।श्री मौर्य ने कहा कि प्रदेश में तीन करोड़ परिवारों की महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से जोड़ने का व्यापक अभियान संचालित किया जा रहा है। इस लक्ष्य को और अधिक गति देने के लिए मिशन स्तर से सभी जनपदों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए जा रहे हैं।उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के मिशन निदेशक अरुण कुमार ने कहा कि ग्राम संगठनों की संख्या में वृद्धि प्रदेश में मजबूत, आत्मनिर्भर एवं प्रभावी सामुदायिक संस्थाओं के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इससे स्वयं सहायता समूहों को बेहतर संस्थागत सहयोग मिलेगा तथा ग्रामीण विकास और महिला सशक्तिकरण के लक्ष्यों को और अधिक प्रभावी ढंग से प्राप्त किया जा सकेगा।

एलेनहाउस पब्लिक स्कूल में 'एक्वालाइन - वॉटर वंडर्स' जिला स्तरीय अंतरविद्यालयी तैराकी प्रतियोगिता 2026 का भव्य समापन

लखनऊ। एलेनहाउस पब्लिक स्कूल, वृंदावन योजना, लखनऊ में 'एक्वालाइन - वॉटर वंडर्स' जिला स्तरीय अंतरविद्यालयी तैराकी प्रतियोगिता 2026 के पाँचवें संस्करण का भव्य समापन सम्पन्न हुआ। दो दिवसीय इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में विभिन्न शहरों के 70 से अधिक विद्यालयों के 600 से अधिक तैराकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। प्रतियोगिता ने युवा खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा, दृढ़ संकल्प, अनुशासन तथा खेल कौशल का उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए एक प्रभावी मंच प्रदान किया।समापन समारोह के मुख्य अतिथि डॉ सृष्टि धोन पीसीएस उपस्थित रही।अपने प्रेरणादायी संबोधन में उन्होंने विजेता खिलाड़ियों को बधाई देते हुए सभी प्रतिभागियों द्वारा प्रदर्शित अनुशासन, समर्पण, खेल भावना एवं उत्कृष्ट प्रदर्शन की सराहना की तथा उन्हें भविष्य में भी निरंतर श्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया।समारोह का शुभारंभ मुख्य अतिथि के स्वागत एवं सम्मान से हुआ। इसके पश्चात विद्यालय की प्रधानाचार्या सुश्री मनीषा अंथवाल ने अपने संबोधन में सभी प्रतिभागियों, प्रशिक्षकों एवं अभिभावकों का आभार व्यक्त करते हुए खेलों के माध्यम से व्यक्तित्व विकास, आत्मविश्वास तथा अनुशासन के महत्व पर प्रकाश डाला।इसके उपरांत पुरस्कार वितरण समारोह

आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न आयु वर्गों एवं स्पर्धाओं के विजेता खिलाड़ियों को पदक एवं प्रमाण-पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। प्रतियोगिता की प्रतिष्ठित चैंपियनशिप ट्रॉफी एलपीसी गोमती नगर को प्रदान की गई।कार्यक्रम का समापन धन्यवाद ज्ञापन एवं राष्ट्रगान के साथ हुआ, जिसके साथ 'एक्वालाइन - वॉटर वंडर्स' के पाँचवें संस्करण का सफल एवं यादगार समापन हुआ।

यह आयोजन विद्यालय की प्रधानाचार्या सुश्री मनीषा अंथवाल, उप-प्रधानाचार्या सुश्री बारबरा अनिबोसी तथा शैक्षणिक समन्वयक श्री अर्चित श्रीवास्तव के कुशल नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ। उन्होंने प्रतियोगिता में सहभागी सभी विद्यालयों, प्रशिक्षकों, निर्णायकों, अधिकारियों, अभिभावकों, स्वयंसेवकों तथा युवा तैराकों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इस आयोजन को सफल बनाने में उनके अमूल्य सहयोग की सराहना की।'एक्वालाइन - वॉटर वंडर्स 2026' का सफल समापन एलेनहाउस पब्लिक स्कूल की खेल संस्कृति, शारीरिक दक्षता, अनुशासन, दृढ़ता एवं उत्कृष्टता को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता का सशक्त प्रमाण है। यह आयोजन युवा खिलाड़ियों को भविष्य में और अधिक ऊँचाइयाँ प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रेरित करता रहेगा।

कार सवार परिवार पर फायरिंग,पुलिस चौकी पहुंचकर बचाई जान

लखनऊ। राजधानी के पारा थाना क्षेत्र में बुधवार दोपहर एक कार सवार परिवार पर हमला किया गया।

मुन्नीलाल द्वारा प्रस्तुत किया गया नाम परिवर्तन का दस्तावेज

रिपोर्ट प्रदुमन दीक्षित जिला संवाददाता कुशीनगर

कुशीनगर जनपद के खड्डा तहसील क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम एकडंगा भजन छपरा निवासी मुन्नीलाल पुत्र रामजतन ने नाम परिवर्तन का दस्तावेज राष्ट्रीय हिंदी समाचार पत्र,जनता का सच, कार्यालय में जमा किया गया है।

शपथ पत्र मैं मुन्नीलाल पुत्र रामजतन ग्राम एकडंगा भजन छपरा पोस्ट – कोहरगड्डी जिला कुशीनगर थाना खड्डा तहसील खड्डा उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी हूँ। मैं अपना नाम मुन्नीलाल से बदलकर पूजन कर लिया है। भविष्य में सभी उद्देश्यों के लिए हमें पूजन के नाम से जाना और पहचाना जाए।

डॉ. शक्ति सिंह साधू (प्रधान सम्पादक), डॉ. प्रवीण (प्रबंध सम्पादक), एडवोकेट शैलेन्द्र श्रीवास्तव (कानूनी सलाहकार), राकेश अग्रवाल (जिला ब्यूरो उत्तर प्रदेश) अब्दुल नासिर स्टेट ब्यूरो उत्तर प्रदेश

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक शक्ति सिंह द्वारा राज तरूण आफसेट, एल0जी0एफ0 5–14, अंसल सिटी सेंटर, हजरतगंज, लखनऊ– 226001 से मुद्रित तथा 486/238–डी, डालीगंज, निरालानगर, जनपद लखनऊ–226020 से प्रकाशित।

सम्पादक– शक्ति सिंह मो0 7052608007 नोटः समाचार पत्र से संबंधित समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र लखनऊ न्यायालय होगा।